वर्ष : 17 ❖ अंक : 137 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
बुधवार, 21 दिसम्बर 2022

महाठग सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा आरोप, कहा- मैंने आप को 60 करोड़ दिए 3

जहरीली शराब मामले की हो सीबीआई जांच : चिराग 8

खेलों के विकास में सहयोग कर रहे हैं सीएम : कुंगा नीमा लेप्चा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 दिसम्बर । आगामी 'सिक्किम प्रीमियर लीग' के आयोजन, राज्य के पांच पूर्व राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं आईएसएल खिलाड़ी के प्रस्ताव और एसवाईए, एसएफए और सिक्किम फुटबॉल डेवलपमेंट प्राइवेट जैसे हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को लेकर राज्य के खेल व युवा मामलों के मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा की अध्यक्षता में स्थानीय सम्मान भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु एआईएफएफ के तकनीकी पहलुओं, मानदंडों, एसएफए और सरकार से सहयोग को पूरा करना है।

बैठक में सिक्किम खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती चुंगचुंग भूटिया, मुख्यमंत्री के सचिव एसडी ढकाल, खेल व युवा मामलों के सचिव राजू बस्नेत, खेल निदेशक श्रीमती डोमा छिरिंग भूटिया के अलावा एसवाईए, एसएफए और सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के अधिकारी एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री लेप्चा ने अपने सम्बोधन में 70 के दशक में फुटबॉल की शुरुआत और मान्यता हेतु पंजीकरण में वृद्धि की बात कही। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनी थी लेकिन उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण खेल व युवा मामलों के विभाग की अध्यक्षता में करने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने खेल विकास हेतु मुख्यमंत्री

प्रेम सिंह तमांग (गोले) के समर्थनों का भी उल्लेख किया।

इसके अलावा एसएफए अध्यक्ष ने भी विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देते हुए अपने कई आवश्यक सुझाव दिये। वहीं सचिव एसडी ढकाल ने भी अपने वक्तव्य में सिक्किम फुटबॉल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एसएफए से सुझाव, समर्थन लेने की बात कही। उन्होंने जानकारी दी कि प्रतियोगिता के सुचारू और सफल संचालन के लिए दोनों पक्षों में एक समझौता किया जाना है।

विद्यार्थियों को संस्कारित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सभी संस्थानों का दायित्व : राज्यपाल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 दिसम्बर । सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद से आज लेफ्टिनेंट जनरल डॉ एके मिश्र, एवीएसएम (रिटायर्ड) रजिस्ट्रार, एसपीयू प्रो रमेश कुमार रावत एवं उप-निदेशक बीओएसएसई श्रीमती एसटी भट्टराई ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। भेंट के आरम्भ में लेफ्टिनेंट जनरल डॉ एके मिश्र ने राज्यपाल का खादा, बुके और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया।

इस भेंट के दौरान राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को संस्कारित, गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना सभी शिक्षण संस्थानों का दायित्व है जिससे वे प्रदेश तथा देश के भविष्य का निर्माण तो कर ही सकेंगे, इसके साथ ही समाज में सकारात्मक सहभागिता निभाते हुए अपने अभिभावक का नाम देश दुनिया में रोशन कर सकेंगे।

इसी के साथ राज्यपाल ने

कॉफ़ी टेबल बुक और गायत्री मंत्र लिखित थांका भी भेंट किया और इसके उच्चारण का नियमित रूप से पालन करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने विभिन्न मंच के माध्यम से प्रदेश, देश, दुनिया के सभी लोगों को गायत्री मंत्र का प्रतिदिन नियमित रूप से उच्चारण करने कि प्रेरणा लम्बे समय से देते आ रहे हैं।

सिक्किम एवं यहां के लोगों की रक्षा करने वाली एकमात्र पार्टी है एसडीएफ : शेरपा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 दिसम्बर । स्थानीय 26 आरिथांग निर्वाचन क्षेत्र में आज सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। एसडीएफ के आरिथांग क्षेत्रीय सलाहकार लाक्पा शेरपा के लालबाजार स्थित निवास पर पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) और गंगटोक, तादोंग एवं आरिथांग प्रभारी ओटी लेप्चा ने इसका उद्घाटन किया। एसडीएफ के प्रचार महासचिव विष्णु दुलाल ने एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी।

इस अवसर पर लेप्चा ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और लाक्पा शेरपा एवं एसडीएफ परिवार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय चलाने के लिए जगह उपलब्ध कराकर पार्टी अध्यक्ष ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी कार्यालय का संचालन स्थानीय लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान समय में एसडीएफ पार्टी ही सिक्किम एवं यहां के लोगों की

रक्षा करने वाली एकमात्र पार्टी है।

वहीं अपने वक्तव्य में राज्य की मौजूदा एसकेएम सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लेप्चा ने वर्तमान एसकेएम सरकार को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में अनुशासनहीन बताया। उन्होंने कहा कि एसकेएम शासन में राज्य अब आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया है, लोगों की स्थिति कमजोर एवं (शेष पृष्ठ ०३ पर)

रोलू क्रांति परिवर्तन की धरातल है। रोलू दिवस एक शाश्वत क्रांति का पर्याय है जो अटूट आस्था के पवित्र स्थान से शुरु होकर सिक्किम के भाग्य और भविष्य का निर्धारण करेगा। लोकतांत्रिक देश का 22वां राज्य होने के बावजूद स्वतंत्रता से वंचित सिक्किम के लिए रोलू की क्रांति ने जनता की आवाज परिवर्तन को लक्षित सिक्किम को एक अडिग नेतृत्व प्रदान किया है।

2009 में, सत्तासीन डेमोक्रेटिक पार्टी की अलोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर लोगों की क्रांति को जन्म देना बेहद कठिन था। तमाब बाधाओं और दमनकारी राजनीतिक माहौल के बीच, रोलू की आस्था और क्रांतिकारियों ने सिक्किम की राजनीतिक यात्रा में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। क्रांति के अटल योद्धा सिक्किम कांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के पार्टी अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) रोलू की पावन भूमि पर किए गए समझौते और क्रांतिकारी साथियों के साथ उनकी साझा रणनीति से सिक्किम में बदलाव का आंदोलन शुरु हुआ। पिकनिक की लहर से शुरु हुई अजेय क्रांति को सिक्किम की जनता ने सत्ता की बागडोर सौंप दी। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के सफल नेतृत्व में पहले साढ़े तीन साल में जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के संकेतों को स्वीकार करना शुरु कर दिया है। अनेक चुनौतियों से जूझते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ सर्वांगीण विकास का जो परिवर्तन दिख रहा है उसका मूल मंत्र रोलू की ही क्रांति की उपज है।

मल्ली जोरथांग में स्थित पवित्र रोलू मंदिर परिसर के पास मनाया जाने वाला रोलू दिवस आज सिक्किम के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक त्योहार बन गया है। इस अवसर पर हर साल हजारों लोग पार्टी की विचारधारा को आत्मसात कर एसकेएम में शामिल होते हैं। हर साल आज के दिन रोलू नदी के तट पर लोगों का जन समुद्र उमड़ता है। जनता की अपरा भीड़ सिक्किम के सभी विधानसभा का नेतृत्व करती है, जबकि विकास और व्यवस्था परिवर्तन के एक मात्र लक्ष्य को लेकर काम कर रहे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के नेता श्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) का अटूट नेतृत्व और विकास का दर्शन सिक्किम माता का वरदान और सिक्किम के लोगों का सौभाग्य।

कल के सिक्किम की प्रगति और रोलू क्रांति के बीच एक अकाट्य संबंध है। आज के मुक्त वातावरण में फलती-फूलती लोकतान्त्रिक व्यवस्था को लाने वाले क्रान्ति की यात्रा में हमने समय की गति के साथ अनेक महान योद्धाओं को खोया है। दिवंगत महानुभावों द्वारा पार्टी को दिए गए अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। एसकेएम के उन सभी साथी यात्रियों के परिवारों द्वारा अनुभव की गई पीड़ा हमारी भी पीड़ा है। लेकिन हमें जीवन और मृत्यु के ध्रुवीय सत्य को भले ही स्वीकार करना पड़े, लेकिन उनका त्याग और बलिदान हम क्रांतिकारियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा।

रोलू क्रांति से जन्मी विकास यात्रा में हम भागीदार बन रहे हैं। सिक्किम के स्वस्थ जीवन से लेकर माताओं के लिए आर्थिक सहयोग, गरीबों के लिए घर और युवाओं के लिए उद्यमिता के अवसर, अध्ययन, अनुसंधान का संस्थागत विकास, कृषि और पशुपालन के जीवनदायी पेशे को पूरा सहयोग देकर सिक्किम के जीवनदायिनी पेशे, एक नए, विपणन योग्य सिक्किम के निर्माण के महान कार्यों तथा व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित शुरुआत के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है।

पश्चिम सिक्किम के 04-गेजिंग बर्मेक विधानसभा के सभी अत्यंत आदरणीय जनता की ओर से 14वें रोलू दिवस के शुभ अवसर पर, मैं रोलू क्रांति के प्रणेता श्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) जी को हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। सभी क्रांतिकारी साथियों को रोलू दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जय एसकेएम
जय पीएस गोले

जदयू सांसद ललन सिंह ने जहरीली शराब मामले में संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में जांच करने की बात की है जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है।

उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनकी बात का विरोध किया और फिर दोनों के बीच नोकझोंक देखने को मिली।

बिहार के मुंगेर से लोकसभा सदस्य राजीव रंजन सिंह ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को सूचना दी है कि वह छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मौत के मामलों की जांच करेगा। यह मानवाधिकार आयोग का मामला कहां से आ गया?

उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए।

सिंह ने कहा, अगर बिहार के मामले की मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है तो कर्नाटक के मामले की जांच क्यों नहीं कर रहा, मोरबी (गुजरात) की पुल दुर्घटना की जांच क्यों नहीं कर रहा?

उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सत्तापक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों ओर के सदस्यों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई।

सदन में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने झारखंड में जैन धर्म के पवित्र स्थान सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विषय उठाया और कहा कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि इस स्थान की शुद्धता और पवित्रता बनी रह सके।

इस पर पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, हम झारखंड सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमने कोई घोषणा नहीं की है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मवेशियों के चारे की मूल्य वृद्धि का विषय उठाया और कहा कि गाय के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी इस मामले में ध्यान नहीं दे रही।

भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सेना में अहीर रेजीमेंट बनाने की मांग एक बार फिर सदन में उठाई।

जैकलीन की विदेश जाने की मांग 22 दिसम्बर तक स्थगित : दिल्ली अदालत

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा की अनुमति मांगने वाली फर्नांडीज के आवेदन पर जवाब मांगा।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान फर्नांडीज भी अदालत के समक्ष पेश हुई। 12 दिसंबर को, अदालत ने धन उगाही मामले में उनकी सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। उसी दिन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी मामले के सिलसिले में चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया था।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 2 फरवरी, 2023 को अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए पुलिस से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। 30 नवंबर को, दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया, जिसने चंद्रशेखर को फर्नांडीज से मिलवाया।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पिछले साल चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के प्रावधानों के तहत चंद्रशेखर, लीना मारिया समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।

उसने पत्नियों अदिति सिंह और जपना सिंह को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में दिखाकर और उनके पतियों के लिए जमानत सुनिश्चित करने के लिए कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

ईओडब्ल्यू के मुताबिक, लीना, सुकेश और अन्य लोगों ने ठगी से कमाए गए पैसे के लिए शेल कंपनियां बनाकर हवाला रूट का इस्तेमाल किया।

प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान में बांके बिहारी मंदिर से न हो कोई छेड़छाड़ : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मंदिर क्षेत्र में सरकार की विकास करने की योजनाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान में बांके बिहारी जी के मूल मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। साथ ही बिहारी जी मंदिर की पूजा अर्चना में लगे सेवायतों के मंदिर प्रबंधन में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

मंदिर के आसपास की जो जमीन क्षेत्र के विकास के लिए खरीदी जाएगी, वह ठाकुर जी महाराज के ही नाम से रहेगी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने याची अनंत शर्मा तथा कई अन्य सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

हाईकोर्ट से पारित पूर्व आदेश के क्रम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल की ओर से मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास के लिए एक प्लान प्रस्तुत किया।

पूर्व जज की ओर से दी गई रिपोर्ट में मंदिर में भीड़ भाड़ के मद्देनजर उसे नियंत्रित करने तथा मंदिर के आसपास के पांच एकड़ एरिया को विकसित करने को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मंदिर के पुजारियों, सेवायतों की ओर से कहा गया कि उनका मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास करने तथा दर्शनार्थियों के हित में किए जा रहे कार्यों का कोई विरोध नहीं है। उनकी आपत्ति केवल इस बात को लेकर है कि ठाकुर बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने न केवल बांके बिहारी मंदिर बल्कि उससे सटे हुए अन्य प्रमुख मंदिरों के साथ भी छेड़छाड़ न करने को कहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि लगभग 250 करोड़ रुपये बांके बिहारी जी के नाम से जमा हैं।

कोर्ट ने सरकार से मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने तथा भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार से एक विस्तृत प्लान मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले पर अब 17 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगी।

बिजली बोर्ड के दफ्तर बंद होने पर कोर्ट जाएंगे : जयराम ठाकुर

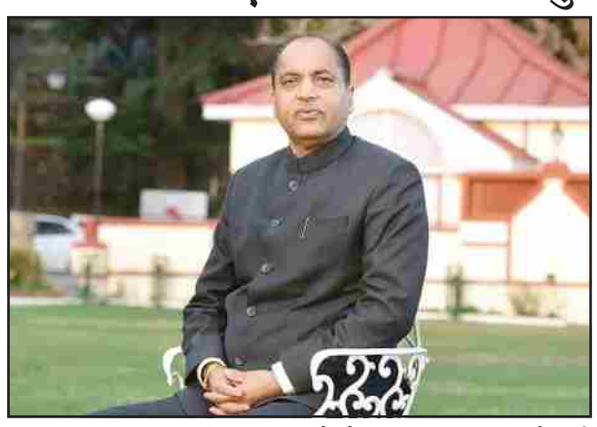

शिमला, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बिजली बोर्ड के कई दफ्तर बंद कर दिए गए। इसका भाजपा कड़ा विरोध करती है और सरकार के इस फैसले के विरोध में कोर्ट जाएंगे। एक-एक कर सभी संस्थान बंद करने के फैसले पूर्ण रूप से सरकार की तानाशाही को दिखाते हैं। पूर्व सीएम ने जारी एक बयान में कहा कि ये सभी डिवीजन और सब डिवीजन बोर्ड की बैठक में सरकार की मंजूरी के बाद खोले गए थे। दूसरी ओर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अलग बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया कि यह सरकार सिर्फ पूर्व सरकार के लिए गए निर्णय पलटने आई है। भाजपा इसकी निंदा करती है। सुक्खू सरकार ने धर्मपुर स्थित शिवा प्रोजेक्ट का पहला कार्यालय बंद कर कर्मचारियों को शिमला बुला लिया। एक्सीलेंस केंद्र बंद कर दिया। इस सरकार को जनहित की चिंता नहीं है। भाजपा के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ।

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार पर भाजपा सरकार के खोले कार्यालय डिनोटिफाई करने का फैसला वापस नहीं लिया तो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस सरकार को चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनी में तालाबंदी हो गई है। इससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट है। कांग्रेस सरकार समस्या के समाधान के स्थान पर दिल्ली और राजस्थान घूम रही है। सरकार अपने पहले मंत्रिमंडल के गठन करने के कार्य में नाकाम रही है। जन विरोधी निर्णय लेने में वह आगे है। सरकार ने बिजली बोर्ड के दफ्तरों को डिनोटिफाई किया है।

बागवानी और जल शक्ति विभाग के शिवा प्रोजेक्ट के धर्मपुर में चल रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को भी डिनोटिफाई किया गया है। सरकार अपने जन विरोधी निर्णयों पर पुनर्विचार करे। उप मुख्यमंत्री 10 दिन के अंदर ओपीएस बहाल करने की बात कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री कैबिनेट बनाने की दुहाई देकर कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान गए कांग्रेस नेता और विधायक कोरोना प्रोटोकोल का पालन करें। यदि प्रदेश में फिर से कोरोना फैलता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।

सीएम हेमंत की ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और डोमिसाइल पॉलिसी बिल पर मंजूरी की मांग

रांची, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और डोमिसाइल एवं इंप्लॉयमेंट पॉलिसी के विधेयकों पर सहमति प्रदान करने और इन्हें केंद्र सरकार के पास भेजने की मांग को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 40 सदस्यों वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की।

ये दोनों विधेयक बीते 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए थे। इन विधेयकों को इस संकल्प के साथ पारित कराया गया था कि इन्हें संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र इन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल करा देता है तो ये दोनों विधेयक कानून का रूप ले लेंगे। बता दें कि नौवीं अनुसूची में शामिल होने वाले कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

फिलहाल विधानसभा से पारित ये दोनों विधेयक राज्यपाल के पास विचारार्थ हैं। इन दोनों विधेयक अगर कानून का रूप ले लेते हैं तो राज्य में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की शत प्रतिशत सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हो जाएंगी और राज्य में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी हो जाएगा। स्थानीय नीति विषयक विधेयक के मुताबिक झारखंड में स्थानीय निवासी उन्हें माना जाएगा, जिनके पूर्वजों के नाम 1932 या उसके पूर्व राज्य में हुए भूमि सर्वे के कागजात (खतियान) में दर्ज होंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने उनसे आग्रह किया कि वे इन विधेयकों पर जल्द से जल्द अनुमोदित कर केंद्र सरकार के पास अग्रसारित कर दें। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये दोनों विधेयक झारखंड के आदिवासियों और मूल निवासियों को उनका वाजिब हक दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। राज्य में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जो नहीं चाहते कि झारखंड के स्थानीय लोगों को उनका अधिकार मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी, लेकिन इसे बाहर के राज्यों के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे ही लोग हमारी पॉलिसियों के खिलाफ अदालत में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल में उच्च न्यायालय में हमारी नियोजन नीति खारिज हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस मामले में न्यायालय में याचिका दायर करने वाले 20 लोगों में से सिर्फ एक झारखंड का है। बाकी लोग दूसरे राज्यों के हैं।

मुख्यमंत्री से राज्यपाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा से भी शामिल होने की अपील की थी, लेकिन भाजपा ने 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए प्रतिनिधिमंडल से खुद को अलग रखा।

प्रतिनिधिमंडल में झामुमो, कांग्रेस, राजद, आजसू पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, भाकपा माले सहित अन्य दलों के नेता शामिल थे। इनमें मंत्री आलमगीर आलम, डॉ रामेश्वर उरांव, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मथुरा महतो, विधायक अंबा प्रसाद, अनूप सिंह, विनोद सिंह आदि प्रमुख थे।

एससी-एसटी कोटा बढ़ाने का बिल कर्नाटक विधानसभा में हुआ पेश, विपक्ष ने उठाए सवाल

बेलगावी, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। महाराष्ट्र के साथ ताजा सीमा विवाद को लेकर हंगामे के बीच कर्नाटक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी जारी है। चुनाव के लगभग पांच महीने के पहले हो रहा यह सत्र भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र के सीमा विवाद चल रहा है और मौजूदा भाजपा सरकार का यह आखिरी सत्र होगा। वहीं, सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाने का बिल कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया।

एससी-एसटी के लिए आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी के लिए लागू अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बोम्मई सरकार ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक, 2022 पेश किया। गौरतलब है कि अक्तूबर माह में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सरकार ने को सर्वसम्मित से राज्य में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण 15 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 3 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। है। उससे पहले, कर्नाटक कैबिनेट ने बीते आठ अक्तूबर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक सहमति दे दी थी। अब अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश को जारी कर दिया जाएगा।

बिल में कहा गया है कि चूंकि मामला जरूरी था और उस समय राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं थे। ऐसे में अध्यादेश को 23 अक्टूबर की अधिसूचना के माध्यम से प्रख्यापित किया गया था। साथ ही अध्यादेश के सभी प्रावधान 1 नवंबर से लागू भी हो गए थे। अब जबकि विधानसभा का सत्र जारी है तो अध्यादेश को बिल के रूप में परिवर्तित किया जाए।

राज्य सरकार ने यह फैसला न्यायमूर्ति एच. एन. नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। इस आयोग ने एससी आरक्षण 15 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी करने की सिफारिश की थी, इसके अलावा एसटी आरक्षण को 3 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने की सिफारिश की थी। आयोग ने जुलाई 2020 में सरकार को अपनी सिफारिशें दीं थीं।

बोम्मई सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में आरक्षण की संख्या 56 प्रतिशत तक चली जाएगी। हालांकि एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत तय की थी। ऐसे में विपक्षी दल सरकार से सवाल कर रहे हैं कि वे इसे कैसे लागू करेंगे।

विपक्ष इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव के लिए याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कदम राजनीति से प्रेरित है और इसका कोई वास्तविक सरोकार नहीं है।

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का आरोप, जजों को ब्लैकमेल करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल रही है सरकार

औरंगाबाद, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार न्यायाधीशों की कमजोरियों को खोजने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में समाजवादी नेता बापूसाहेब कालदाते की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में संविधान के तहत स्वायत्तता प्राप्त संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

प्रशांत भूषण ने कहा कि जब सरकार को लगता है कि कोई न्यायाधीश उसके हिसाब से काम नहीं करेगा, तो वह ऐसे न्यायाधीश को शीर्ष स्थान पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले, आयोगों या अन्य निकायों में सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को नियुक्ति का लालच देकर उनके निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने नया तरीका अपनाया है। अब सभी न्यायाधीशों की फाइल तैयार की जाती है। आईबी, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों से न्यायाधीशों या उनके रिश्तेदारों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए कहा जाता है।

उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसी कोई कमजोरी सामने आती है तो उसका इस्तेमाल उस जज को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिशों का विरोध करने के लिए लोगों को एक साथ आना चाहिए।

भूषण ने दावा किया कि जब हमने अपने संविधान को अपनाया, तो कई संस्थान बनाए गए और उन्हें स्वायत्त दर्जा प्राप्त है। लेकिन अब उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले जब विधेयकों का मसौदा तैयार किया जाता था तो उन्हें संसदीय समितियों के पास भेजा जाता था और उन पर चर्चा की जाती थी, लेकिन अब उन्हें बिना चर्चा के पारित कर दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पहले काफी स्वायत्त था, लेकिन अब सरकार चुनावों की तारीखें तय कर रही है।

सभी 10 गारंटियां पूरी करेंगे, पहली कैबिनेट में ही देंगे ओपीएस : सीएम सुक्खू

शिमला, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। कोरोना संक्रमित होने के चलते हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटीन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करने के बाद मैं जल्द काम पर लौटूंगा। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से दी गई सभी 10 गारंटियां पूरी करेंगे और पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की जाएगी। मंगलवार को नई दिल्ली से जारी प्रेस बयान में मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र 2022 में कर्मचारियों की ओपीएस की लंबित मांग के संबंध में किए गए वादे को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरा किया जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि राज्य के वित्त विभाग को प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों की सुविधा के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और समाज के अन्य वर्गों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है। एक व्यवहार्य और व्यापक योजना तैयार करने में अधिकारी जुटे हैं। उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरण हितैषी वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा मिलेगा और सचिवालय और अन्य विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक समुदाय को प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को उन्नत तकनीक के साथ सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा में नेता प्रतिपक्ष बनने की होड़ लगी हुई है। यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ कौन नेता अधिक हल्ला कर सकता है। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता अपनी हार के कारणों का पता लगाने के बजाय कांग्रेस की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। उन्हें सिर झुका कर हार को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार स्थिर और स्थायी है।

जल्द ही विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। उसके बाद सभी कार्य सुचारु रूप से चलेंगे। अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ऊना जाते समय नालागढ़ में रुके, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका

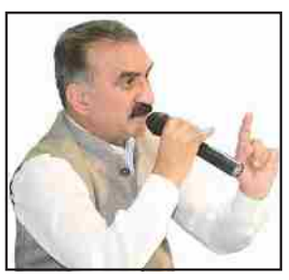

जोरदार स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भी 10 गारंटियां चुनाव से पहले जनता को दी हैं, उनको लागू किया जाएगा। जल शक्ति, ट्रांसपोर्ट और भाषा एवं संस्कृति विभागों का अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद नीतियों में बदलाव लाया जाएगा।

एम्स दरभंगा के लिए बिहार सरकार ने अब तक उपलब्ध नहीं कराई 200 एकड़ जमीन : सुशील मोदी

पटना, 20 दिसम्बर (का.सं.)। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में ही दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन बिहार सरकार ने एम्स बनाने के लिए अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया है। गौरतलब है कि दरभंगा में एम्स बनने के बाद उत्तर बिहार और मिथिलांचल वासियों को काफी लाभ पहुंचेगा। मंगलवार को राज्यसभा में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से दरभंगा एम्स के विषय में जानकारी मांगी। सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने बताया कि दरभंगा एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार को 200 एकड़ भूमि सभी तरह की बाधा से मुक्त उपलब्ध कराना था। लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि एम्स दरभंगा का कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया है।

सुशील कुमार मोदी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1264 करोड़ रुपया की अनुमानित लागत से एम्स दरभंगा की स्थापना को सितंबर 2020 की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि एम्स दरभंगा को 750 बिस्तर वाला अस्पताल बनाए जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रस्तावित अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी के साथ-साथ शैक्षणिक ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आवासीय ब्लॉक, छात्रावास, अतिथि गृह और रात्रि विश्राम गृह शामिल है।

बता दें कि बिहार में दूसरे एम्सजैसे अस्पताल की मंजूरी केंद्र सरकार ने 2015 के बजट में दी थी। इसके बाद अगले तीन साल तक इसके लिए राज्य में जगह खोजने का काम किया गया। फिर 2018 में बिहार सरकार ने दरभंगा के डीएमसीएच की जमीन पर राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूर करते हुए 2020 में इसके लिए राशि स्वीकृत की थी। इसके बाद जनवरी 2022 में डीएमसीएच में एम्स निर्माण के लिए मिट्टी भराई का काम शुरू किया गया।

गौरतलब है कि दरभंगा एम्स बन जाने के बाद न सिर्फ बिहार के 15-16 जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बल्कि पड़ोसी राज्य के साथ पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी दरभंगा एम्स के बन जाने से लाभ होगा।

मिल्क यूनियन की बोर्ड बैठक आयोजित

अनुगामिनी नि.सं.

मंगन, 20 दिसम्बर । उत्तर जिला मिल्क यूनियन के सभागार में सोमवार को यूनियन की बोर्ड बैठक आयोजित की गई जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों के अलावा पशुपालन व पशु चिकित्सा विभागीय सचिव पी सेंथिल कुमार, प्रधान निदेशक, संयुक्त सहकारिता रजिस्ट्रार एवं एनडीएमयू के एमडी ने भाग लिया।

इस दौरान एनडीएमयू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बैठक के एजेंडे की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य वर्तमान भौतिक, वित्तीय और मानव संसाधन की स्थिति, प्रसंस्करण तथा विपणन की स्थिति और एनडीएमयू की परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा एवं समीक्षा करना और भविष्य के कदमों पर विचार करना था।

बैठक में पशुपालन व पशुचिकित्सा सचिव पी. सेंथिल कुमार ने राज्य के डेयरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देते हुए सिक्किम सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ और एनडीएमयू को एकीकृत करने की संभावना बतायी जिससे कि उत्तर सिक्किम तक भी विभिन्न सरकारी सुविधाओं पर्याप्त लाभ पहुंचाया जा सके।

इसके अलावा बैठक में खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में एनडीएमयू के समक्ष पेश आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही इसमें संघ की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा के साथ ही इसके सुधार हेतु विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। वहीं दूध खरीद का वर्तमान आर्थिक अव्यवहारिक स्थिति के मद्देनजर मिल्क यूनियनों और सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए मंगन जिला डेयरी विकास के एकीकरण और सुदृढ़ीकरण के विभिन्न उपायों पर भी बात की गई।

इसके पश्चात विभागीय सचिव ने जिले में डेयरी विकास में प्रयास का उपयोग करने के उद्देश्य से सभी विभागीय अधिकारियों, ब्लॉक परियोजना प्रबंधकों एवं सिक्किम ग्रामीण आजीविका मिशन की पासु सखियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें जिले में डेयरी क्षेत्र में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सचिव ने विभागीय अधिकारियों, मिशन अधिकारियों और पासु सखियों को उद्देश्यों को प्राप्त करने में भूमिकाओं के बारे में बताया। वहीं बैठक में सभी प्रतिभागियों ने डेयरी क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान की दिशा में अपने सुझाव भी दिये।

इसके अलावा विभागीय सचिव, प्रधान निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं अन्य अधिकारियों ने जिले के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों और चांदे लाइवस्टॉक फार्म का दौरा भी किया।

विधायक गोले ने लाभार्थियों को प्रदान की दुधारू गाय

अनुगामिनी नि.सं.

सोरेंग, 20 दिसम्बर । जिले के दोदक में आयोजित एक कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में सोरेंग-च्याखुंग विधायक आदित्य गोले ने 25 लाभार्थियों में दुधारू गायों और बछड़ों का वितरण किया। इस अवसर पर पंचायत सदस्यों के अलावा सोरेंग डीसी भीम ठटाल, पशुपालन व पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. किशोर थापा, सोरेंग बीडीओ एसके शर्मा, पशुपालन व पशु चिकित्सा विभाग के उपनिदेशक डॉ. प्रेयना गुरुंग एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम में अपने संक्षिप्त भाषण में विधायक गोले ने योजना को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु पशुपालन व पशु चिकित्सा विभाग के साथ ही उपस्थित सभी लाभार्थियों को बधाई दी। उन्होंने इसे पूरे समुदाय के लिए विकास एवं समृद्धि की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से राज्य में पिछड़े आदिवासी समुदाय के लिए ऐसी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन एवं सोरेंग को हाल ही में जिला बनाने के लिए प्रेम सिंह तमांग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वहीं इस दौरान विधायक ने लाभार्थियों को वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रदान की गई सहायताओं एवं लाभों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

अजय राय की स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी का एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (एजेप्सी)। कांग्रेस नेता अजय राय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए अजय राय को नोटिस भेजकर 28 दिसंबर को आयोग के सामने पेश होने कहा है।

बता दें कि अजय राय ने अमेठी सीट को लेकर स्मृति ईरानी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा की गई एक विवादास्पद टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग को कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली हैं। आयोग ने अजय राय द्वारा की गई महिला विरोधी टिप्पणी का संज्ञान लिया है।

आयोग ने कहा कि राय द्वारा की गई टिप्पणियां बेहद अपमानजनक हैं और आयोग ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग ने इस मामले में सुनवाई भी निर्धारित की है और अजय राय को 28.12.2022 को दोपहर 12 बजे तक आयोग के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है अजय राय ने सोमवार को सोनभद्र में केंद्रीय मंत्री पर व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणी की थी। राय ने कहा था कि, राहुल गांधी, राजीव गांधी इस सीट (अमेठी) पर चुनाव लड़े हैं, कई कल-कारखाने लगाए गए। अब आधे से ज्यादा कल-कारखाने बंद पड़े हुए हैं, स्मृति ईरानी केवल आती हैं और लटके-झटके देकर चली जाती हैं।

आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है : भीम ठटाल

अनुगामिनी नि.सं.

सोरेंग, 20 दिसम्बर । आधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हेतु सोरेंग डीसी भीम ठटाल की अध्यक्षता में आज यहां पहली जिलास्तरीय आधार निगरानी समिति (डीएलएएमसी) की बैठक सम्पन्न हुई।

इसमें एसडीपीओ बिमल गुरूंग, डीसीएसओ जेएम सुब्बा, यूआईडीएआई (डीईएसएमएंडई) के पीएम थुप्टेन गेलेग, सहायक निदेशक नीमा छिरिंग तामंग, सहायक निदेशक (डीईएसएमएंडई) पीएस सुब्बा, सहायक शिक्षा निदेशक सीटी शेरपा, सहायक यूआईडीएआई प्रबंधक नयनमणि दास के अलावा अन्य अधिकारी एवं प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

इस अवसर पर डीसी श्री ठटाल ने जिले में यूआईडी कार्यक्रम की समीक्षा की और विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए आधार कार्ड प्राप्त करने के महत्व एवं विभिन्न आधिकारिक उपयोगों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आधार कार्ड को किसी व्यक्ति के नागरिकता प्रमाणपत्र के तौर पर स्थापित करने पर विचार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जिले में आधार कवरेज की प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी ली।

इसके अलावा डीसी ने आंगनमा प्रशासन योजना के एक हिस्से के तौर पर आधार नामांकन की कम संख्या वाले चिन्हित क्षेत्रों में और अधिक कार्यशालाओं और शिविरों के आयोजन सुनिश्चित करने की सलाह भी दी। वहीं श्री गेलेग ने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन के उद्देश्य से हाल ही में शुरू किए गए 'मेरे बच्चे के लिए आधार' अभियान के बारे में जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि जिले में कुल तीन समर्पित आधार केंद्र दरमदीन, मंगलबरिया और सोरेंग में होंगे।

सिक्किम एवं यहां .....

दयनीय हो गई है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने देश के संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य के विशेष कानूनी प्रावधानों को भी खतरे में डाल दिया है। उनके अनुसार एसकेएम पार्टी के मंत्री और नेता सिर्फ लोगों की भीड़ जुटाने में लगे हैं और एसकेएम सरकार से सिक्किम को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

एनएचआरसी पर गरम सत्ताधारी दल, आरजेडी ने बताया 'भाजपा' धिकार आयोग

पटना, 20 दिसम्बर (का.सं.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पर बिहार में सियासी बयानबाजी हो रही है। सारण जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है। इससे संबंधित मामले की जांच के लिए मानवाधिकार आयोग की टीम पटना पहुंची। छपरा जाकर पुलिस की भूमिका की जांच करेगी। राज्य में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 से ऊपर पहुंच चुकी है। 2016 में लागू किए गए पूर्ण शराब बंदी के बाद जहरीली शराब से हुए मौत की सबसे बड़ी घटना है।

राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ही जहरीली शराब से मौत बिहार के मुकाबले अन्य राज्यों में ज्यादा हुई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक जहरीली शराब से सर्वाधिक मौत भाजपा शासित राज्यों में हुई।

मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात में जहरीली शराब से मौतें ज्यादा हुई है। लेकिन मानवाधिकार आयोग की कोई भी टीम बीजेपी शासित राज्यों में नहीं गई। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। जहरीली शराब से मौत होने के बाद मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंची है। क्या मानवाधिकार आयोग 'भाजपाधिकार' आयोग बन गया है?

राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के इशारे पर नाचती हैं, ये अब पूर्ण रूप से साबित हो चुका है। भाजपा शासित राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों पर फोकस नहीं करती है। बिहार में शराब माफिया के पक्ष में गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी शराब चालू कराना चाह रही है। जबकि यही बीजेपी और इनकी पीआर एजेंसी गुजरात में शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत पर बैन को जायज ठहरा रही है। सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी हर अनैतिक कार्यों को सही ठहराने पर आमादा है।

छपरा जहरीली शराबकांड में मौत और पुलिस की भूमिका की जांच के लिए पहुंची एनएचआरसी की टीम को लेकर सत्ताधारी दल के नेता गरम हैं। कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि उन्हें जांच से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनएचआरसी (एनएचआरसी) का काम है, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना। प्रेमचंद मिश्रा ने ये सवाल उठाया था कि क्या छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौत मानव के अधिकार का उल्लंघन है? आखिर आयोग की टीम यहां किस बात की जांच कर रही? उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब से मौतें उन राज्यों में भी हो रही है, जहां शराबबंदी कानून लागू नहीं है। इसलिए मानवाधिकार का कहीं उल्लंघन हुआ है तो वो हरियाणा और यूपी में हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन राज्यों में मौत की जांच क्यों नहीं कर रहा?

चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, कोविड-19 के सभी मामलों की होगी जीनोम सिक्वेंसिंग

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिख देश में कोरोना के सभी पॉजिटिव मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग करने को कहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि जापान, अमेरिका, कोरिया रिपब्लिक, ब्राजील और चीन में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूरी है कि देश में सामने आ रहे कोरोना के पॉजिटिव केसों की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए। इससे कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में समय से जानकारी मिल सकेगी।

प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा है कि सभी राज्यों से यह आग्रह किया जाता है कि वह जहां तक संभव हो रोजाना कोरोना के पॉजिटिव मामलों के सैंपल निर्धारित, जीनोम सिक्वेंसिंग लैबोरेट्री में भेजना सुनिश्चित करें। पत्र में कहा गया है कि इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में हर संभव मदद की जाएगी।

देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 112 नए मामले सामने आए हैं। नए केस आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,199 पर पहुंच गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,490 रह गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से तीन और मरीजों की मौत से देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,677 हो गई है। मौत के नए मामलों में केरल में दो और महाराष्ट्र में एक मरीज की जान गई। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत है। वहीं, कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 98.8 प्रतिशत हो गई है। बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 69 की कमी दर्ज की गई है।

चीन में कोरोना विस्फोट से स्थिति भयावह हो गई है। स्थिति यह है कि वहां अस्पतालों में लोगों को एडमिट करने के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं। चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि 1 शख्स 16 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर रहा है। चीन में कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट ने भारी तबाही मचाई है।

चीन में कोरोना के कोहराम का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वी चीन के अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना से अगले साल मार्च तक 10 लाख लोगों की जान जाने की आशंका है।

महाठग सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा आरोप, कहा- मैंने आप को 60 करोड़ दिए

राजेश अलख

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर । महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने कहना है कि उन्होंने आप को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। महाठग ने ये आरोप दिल्ली में कोर्ट से निकलते वक्त लगाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में एक अन्य आरोपी पिंकी ईरानी के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं जमा होने का मामला कोर्ट के समक्ष उठाया गया। साथ ही वाइस सैंपल की रिपोर्ट का भी इंतजार है। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट जमा कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट अब 6 जनवरी को सुनवाई करेगी।

इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राज्यसभा सीट के बदले 50 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए थे। इसमें महाठग ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा है कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं, तो फिर अपने मुझ जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपये क्यों लिए?

साथ ही कहा कि आपने मुझसे और कारोबारियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए कहा था। सुकेश ने यह भी बताया था कि इसके बदले में आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में एक बड़ा पद ऑफर किया गया था।

सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया था। मैं तिहाड़ जेल में बंद था। सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल मंत्री थे। वे कई बार जेल आए और मुझसे कहा कि मैं जांच एजेंसी के सामने आप को दिए चंदे के बारे में जानकारी न दूं। एलजी को लिखे पत्र में चंद्रशेखर ने कहा, 2019 में सत्येंद्र जैन फिर जेल में आए। उस वक्त उनके साथ उनके सचिव और दोस्त सुशील थे। सत्येंद्र जैन ने मुझसे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मांगे। ताकि मैं जेल में सुरक्षित रह सकूं और मुझे जेल में बेसिक सुविधाएं मिल सकें।

सुकेश ने अपनी चिट्ठी में दावा किया था कि उसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा था कि सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। दबाव के चलते 2-3 महीनों के अंतराल में 10 करोड़ की राशि मुझसे वसूल की गई। सुकेश ने दावा किया कि पूरा पैसा कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी द्वारा लिया गया। इस तरह से मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR TEESTA MORNING
TUESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:108 DrawDate on:20/12/22
1st Prize ₹1 Crore/- 76D 72809
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 72809 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
25623 31347 54473 55381 62300 67407 68674 76211 82032 94087
3rd Prize ₹450/-
1251 1457 4631 5668 5993 6219 7062 7734 7800 8697
4th Prize ₹250/-
0136 0250 0659 3066 3103 4588 6347 6727 7079 8928
5th Prize ₹120/-
0127 0418 0420 0437 0619 0990 1133 1135 1210 1214
1222 1338 1505 1534 1642 1683 1814 1856 1875 1909
1992 2000 2043 2048 2143 2177 2196 2310 2575 2648
2789 2867 2968 3062 3177 3187 3204 3248 3366 3473
3605 3913 3935 3980 4074 4120 4168 4480 4526 4802
5044 5064 5079 5131 5167 5182 5187 5467 5618 5631
6320 6324 6541 6557 6664 6789 6903 6959 7037 7077
7161 7318 7438 7803 7846 7911 8173 8337 8346 8354
8374 8484 8719 8728 8738 8861 8944 8975 9199 9247
9290 9300 9348 9595 9620 9684 9807 9854 9874 9995
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR MOON TUESDAY
WEEKLY LOTTERY
Draw No:108 DrawDate on:20/12/22
1st Prize ₹1 Crore/- 91J 40582
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 40582 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
10551 12203 13835 23259 24756 35582 37652 48258 80563 97009
3rd Prize ₹450/-
0850 1325 2923 3257 4968 5062 5647 6833 7677 9127
4th Prize ₹250/-
0325 1558 2243 2461 2835 2913 3261 8203 8397 9231
5th Prize ₹120/-
0186 0269 0291 0371 0525 0834 0939 1175 1341 1454
1561 1573 1616 1662 1690 1795 2032 2231 2268 2280
2403 2529 2561 2683 2728 2733 2894 2918 2988 3067
3274 3441 3455 3633 3818 3891 3950 4025 4120 4229
4259 4286 4417 4459 4539 4576 4607 4622 4726 4892
4907 4942 5133 5184 5230 5389 5487 5513 5521 5569
5606 5677 5759 5899 6096 6183 6212 6215 6381 6417
6829 6844 6880 7187 7194 7197 7322 7366 7683 7787
7844 7941 8122 8549 8671 8984 9109 9175 9233 9389
9439 9447 9575 9853 9868 9882 9899 9923 9956 9999
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR PARROT EVENING
TUESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:208 DrawDate on:20/12/22
1st Prize ₹1 Crore/- 62E 23017
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 23017 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
18606 21326 26779 34920 47943 65472 70638 90386 92800 92822
3rd Prize ₹450/-
1837 2446 3503 3622 5180 5401 5438 8385 9114 9176
4th Prize ₹250/-
0278 2138 2936 5477 5709 5902 6048 6405 7372 7429
5th Prize ₹120/-
0004 0090 0213 0242 0473 0753 0886 1000 1048 1284
1292 1373 1413 1436 1611 1634 1639 1758 2041 2080
2086 2227 2332 2333 2595 2708 2919 2930 3224 3347
3440 3516 3637 3680 3748 3770 3782 3890 4067 4081
4165 4188 4218 4336 4347 4636 4651 4655 4685 4773
5035 5173 5234 5352 5392 5485 5555 5559 5603 5748
6038 6153 6333 6393 6424 6477 6501 6514 6761 6840
7066 7198 7218 7517 7578 8153 8335 8386 8387 8468
8524 8557 8589 8791 9006 9042 9103 9137 9163 9311
9340 9369 9580 9706 9742 9828 9884 9918 9924 9970
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

जीत का जज्बा

यह बात इस बार के फीफा विश्वकप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी ने साबित कर दिखाया। वे अपनी टीम के साथ विश्व कप जीतने के संकल्प के साथ ही पहुंचे थे। हालांकि हर टीम जीतने के इरादे के साथ ही खेल के मैदान में उतरती है और उसके लिए अपनी सारी ताकत झोंक देती है। मगर मेस्सी ने विश्वकप शुरू होने से पहले ही एक तरह से संकेत दे दिया था कि इस बार की प्रतिस्पर्धा उनके लिए प्रतिष्ठा से जुड़ी है।

विश्वकप से संन्यास की घोषणा भी उन्होंने पहले ही कर दी थी। इसलिए दुनिया भर के खेल प्रेमियों की भावना उनसे जुड़ गई थी। सब यही चाहते थे कि मेस्सी की टीम जीते और वे एक शानदार पारी खेल कर विदा हों। मगर अर्जेंटीना के सामने फ्रांस की टीम एक बड़ी चुनौती थी।

वह पिछली बार की विश्वकप विजेता थी और उसने दुबारा यह खिताब अपने नाम करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसके खिलाड़ियों ने अपनी रणनीतिक कुशलता से अर्जेंटीना के लिए हर कदम पर मुश्किलें खड़ी की। मगर मेस्सी की नेतृत्व कुशलता की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी टीम का मनोबल कमजोर नहीं होने दिया और एक तरह से हारती हुई बाजी अपनी मुट्ठी में कर ली।

निस्संदेह मेस्सी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबाल खिलाड़ियों में हैं। उन्होंने फुटबाल के खेल में कई कीर्तिमान बनाए हैं। सात बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं। मगर उन्हें इस बात का मलाल जीवन में बना हुआ था कि वे अपने देश को विश्वकप नहीं दिला सके। इसी टीस ने शायद उनमें इस बार का विश्वकप जीतने का जज्बा भरा था और आखिरकार वे अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को छत्तीस साल बाद विश्वकप दिलाने में कामयाब हुए। पेले और डिएगो माराडोना के बाद वे पहले ऐसे फुटबाल खिलाड़ी हैं, जिनका जादू पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों के सिर चढ़ कर बोला।

उनके हर गोल पर जश्न मना। वर्षों से मेस्सी की तुलना अर्जेंटीना के फुटबाल खिलाड़ी माराडोना से की जा रही थी कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। हालांकि दोनों के खेलने के अपने अंदाज रहे हैं, मगर माराडोना के साथ एक कीर्तिमान यह जुड़ा हुआ था कि उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने विश्वकप जीता था। फिर यह भी कहा जाता था कि माराडोना देश के लिए ज्यादा जज्बे के साथ खेलते थे और मेस्सी बार्सीलोना के क्लब के लिए। जबकि मेस्सी के पास माराडोना से कहीं अधिक उपलब्धियां हैं।

हालांकि किसी भी खेल में जीत-हार का फैसला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से होता है, मगर जब किसी टीम के साथ दुनिया के खेल प्रेमियों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो उस पर स्वाभाविक रूप से नैतिक दबाव बढ़ जाता है। अर्जेंटीना के साथ भी यही हुआ। वह न केवल इस नैतिक दबाव के साथ मैदान में उतरी थी कि उसे अपने कप्तान को शानदार तोहफा देकर विदा करना था, बल्कि दुनिया भर के फुटबाल प्रेमियों के भरोसे पर भी खरा उतरना था।

इसमें वह कामयाब हुई। खेल का रोमांच अंत तक बना रहा। आखिरकार फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें मेस्सी ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस जीत से मेस्सी निस्संदेह दुनिया के फुटबाल इतिहास में जीवित किंवदंती बन गए हैं और इस तरह वह बहस भी समाप्त हो गई है कि माराडोना और उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है।

जलवायु नुकसान की भरपाई

वेंकटेश दत्ता

इस कोष के संचालन से जुड़े महत्त्वपूर्ण कई मुद्दे बेहद विवादास्पद हैं। इनमें कोष में भुगतान कौन करेगा, कौन इसका लाभ उठा पाएगा और इसे कैसे प्रबंधित किया जाएगा, जैसे प्रश्न शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हानि और क्षति के संबंध में विकासशील देशों की आवाज इस साल मिस्र में अधिक प्रमुखता से उठाई गई। पिछले वर्ष वार्ता के अंतिम दिनों में धनी देशों ने इस तरह के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। चीन, यूरोपीय संघ और कुछ अन्य विकसित देश पहली बार जलवायु हानि और क्षति कोष के समर्थन में सामने आए।

इस तरह अमेरिका ने अपनी लंबे समय से चली आ रही विरोध-नीति को पलट दिया। हानि और क्षति पर सीओपी-27 समझौता महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन बैठक में कई अन्य जरूरी मुद्दों पर बात नहीं हुई। इस बैठक में कमजोर और विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश तो की गई, मगर स्वच्छ ऊर्जा की ओर आवश्यक सहयोग या धन जुटाने के लिए कोई प्रारूप प्रदान नहीं किया गया।

नया नुकसान और क्षति कोष पेरिस समझौते (2015) के तहत, जिम्मेदारी के न्यायसंगत बंटवारे की दिशा में पहला सैद्धांतिक कदम है। भविष्य में यह कैसे विकसित होगा, कहना मुश्किल है। इतना तो तय है कि जलवायु नुकसान और क्षति का मुद्दा विवादास्पद रहने वाला है, जाहिर है, आने वाले समय में कुछ देश इस संकल्प से पीछे हट जाएंगे।

पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं में 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तैंतीस से पैंतीस फीसद तक कम करना शामिल था। विवाद इस बात को लेकर था कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े नुकसान और क्षति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार, यानी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देश कौन हैं, और इन्हें विकासशील देशों को कैसे भुगतान करना चाहिए, जिससे क्षतिपूर्ति की जा सके। यह तो सबको पता है कि इस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अन्य बड़े धनी देश जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं।

सीओपी-27 में चीन की घोषित स्थिति यह है कि वह नुकसान और क्षति कोष का समर्थन तो करता है, लेकिन एक विकासशील देश के रूप में वह कोष में किसी भी योगदान के लिए तैयार नहीं है। सीओपी-27 में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बहुत सारी बहसें और घटनाक्रम हमारे सामूहिक और सतत विकास के मायने तय करेंगे, लेकिन जो बाइडेन और शी जिनपिंग का एक साथ मिलना और नुकसान और क्षति कोष की स्थापना इस बैठक की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

दुनिया की कुल आबादी का सत्रह फीसद होने के बावजूद, भारत वैश्विक उत्सर्जन का लगभग सात फीसद उत्सर्जन करता है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार चीन ग्रीन हाउस गैसों का सत्ताईस फीसद उत्सर्जन करता है, उसके बाद अमेरिका ग्यारह फीसद और फिर भारत 6.6 फीसद करता है। भारत हर साल लगभग तीन गीगाटन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन करता है, इसमें प्रति व्यक्ति योगदान लगभग ढाई टन के बराबर है। यह दुनिया के प्रति व्यक्ति औसत का आधा है। यूएनईपी का अनुमान है कि 2030 तक यह तीन और चार टन के बीच होगा। भारत में कार्बन उत्सर्जन चीन की तुलना में बहुत कम है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। 1901 और 2018 के बीच भारत में औसत तापमान करीब 0.7 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। देखने में यह बहुत कम लगता है, लेकिन प्रकृति के लिए यह बहुत ज्यादा है। ऐसा बदलाव प्रकृति की मुश्किल बढ़ा सकता है। कुछ अनुमानों के अनुसार, वर्तमान सदी के अंत तक भारत में सूखे की गंभीरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 2022 में उत्तर भारत में जो गर्मी की लहर आई थी, उसकी तीव्रता जलवायु परिवर्तन के कारण तीस गुना अधिक थी।

सितंबर-2021 तक भारत अपनी बिजली का 39.8 फीसद अक्षय ऊर्जा स्रोतों से और 60.2 फीसद बिजली जीवाश्म ऱ्इंधन से उत्पन्न करता रहा है, जिसमें से इक्यावन फीसद कोयले से उत्पन्न होता है। भारत में कोयले के खनन के साथ-साथ, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में जलाने के लिए कोयले का आयात भी होता है। नए संयंत्रों के बनने की संभावना नहीं है, पुराने संयंत्रों को बंद किया जा सकता है और बाकी बचे संयंत्रों में अधिक से अधिक कोयला जलाया जा सकता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती से भारत में वायु प्रदूषण तो कम होगा ही, कटौती लागत से चार से पांच गुना ज्यादा स्वास्थ्य लाभ होगा, जो दुनिया में सबसे अधिक सस्ता होगा।

पिछले साल के सीओपी में कोयले को धीरे-धीरे कम करने का संकल्प लिया गया था और इस साल भारत ने सभी देशों को चुनौती दी है कि वे सभी जीवाश्म ऱ्इंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हों। हालांकि, सीओपी का अंतिम बयान केवल एक विविध ऊर्जा-मिश्रण की मांग करता है।

समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे उत्सर्जन में कटौती पर अधिक कार्रवाई की जा सके या जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अधिक वित्तीय या तकनीकी संसाधन जुटाए जा सकें। उत्सर्जन में कटौती पर कुछ मजबूत प्रावधानों को लागू करने के प्रयासों को सभी पक्षों की सहमति नहीं मिली। सभी जीवाश्म ऱ्इंधनों को चरणबद्ध रूप से बंद करने का प्रस्ताव, मूल रूप से भारत द्वारा आगे रखा गया था। इसे बड़ी संख्या में देशों का समर्थन भी हासिल हुआ, पर इसे अंतिम समझौते में शामिल नहीं किया गया।

जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वित्तीय प्रवाह बढ़ाने पर प्रतिबद्धता की कमी सबसे बड़ी चुनौती रही है। शुद्ध-शून्य या नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के रूप में हर साल लगभग चार खरब डालर की आवश्यकता होगी। निम्न-कार्बन विकास पथ में वैश्विक परिवर्तन के लिए हर साल कम से कम चार से छह खरब डालर की आवश्यकता पड़ेगी। विकासशील देशों को ही जलवायु कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए 2030 से पहले लगभग 5.6 खरब डालर की आवश्यकता है। विकसित देशों ने अभी तक प्रति वर्ष सौ अरब डालर की अपेक्षाकृत छोटी राशि देने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया है।

यह समझौता अक्षय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं में अधिक से अधिक निवेश जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार को बदलने की बात करता है। यह सुनिश्चित करता कि जलवायु कोष सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे और कमजोर देशों को आसानी से सुलभ हो। हालांकि अभी इस पर और भी काम करने की जरूरत है।

जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देश अब भी अपने पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। इस कोष के संचालन से जुड़े महत्त्वपूर्ण कई मुद्दे बेहद विवादास्पद हैं। इनमें कोष में भुगतान कौन करेगा, कौन इसका लाभ उठा पाएगा और इसे कैसे प्रबंधित किया जाएगा, जैसे प्रश्न शामिल हैं।

इन सभी मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें धन के स्रोतों की पहचान और विस्तार की संभावना भी शामिल है। कोष का निर्माण वास्तव में महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल पहला कदम है, अभी बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। फिर भी यह एक बड़ी सफलता है।

इस कोष के निर्माण ने विकसित देशों के बड़े प्रदूषकों को एक चेतावनी दी है कि वे अब अपने जलवायु विनाश से बच नहीं सकते। कई देश विनाशकारी तूफान, लू, बाढ़ और बढ़ते समुद्र स्तर का सामना कर रहे हैं।

विकसित देशों को मिल कर काम करना और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नया कोष पूरी तरह से चालू हो सके और जलवायु परिवर्तन से जूझते सबसे कमजोर देशों और समुदायों को जवाब दे सके।

बढ़ती मानव आबादी, घटती जैव-विविधता

वीर सिंह

विगत पांच दशकों में दुनिया में मानव आबादी लगभग दोगुना से अधिक बढ़ गई है, मगर इतने समय में ही वन्यजीवों की आबादी में 69 फीसदी की गिरावट आई है। विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की 2022 की रिपोर्ट में प्रकाशित यह तथ्य धरती पर पारिस्थितिकी तख्तापलट जैसी घटना को दर्शाता है। विश्व वन्यजीव कोष की नवीनतम लिविंग ख्रलेनेट रिपोर्ट के अनुसार, स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचर, सरीसृप और मछली सहित अनेक प्रजातियों की संख्या में 1970 और 2018 के मध्य भारी गिरावट देखी गई है। भारत भी वन्यजीवों के उजड़ने से अछूता नहीं है।

वन्यजीवों की आबादी में निरंतर कमी के पीछे मानव-जनित घटनाओं के साथ जलवायु परिवर्तन भी है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'बढ़ते तापमान पहले से ही बड़े पैमाने पर मृत्यु दर की घटनाओं को बढ़ा रहे हैं, साथ ही जीव प्रजातियों के विलुप्त होने का प्राथमिक कारण बन रहे हैं। प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से वन्य जीवों के नुकसान और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव में वृद्धि की आशंका है।' डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इंडिया के कार्यक्रम निदेशक डॉ. सेजल वोरा के अनुसार, इस अवधि में देश में मधुमक्खियों और मीठे पानी के कछुओं की 17 प्रजातियों की आबादी में गिरावट देखी गई है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट जैव-विविधता के क्षरण के मामले में देश के प्रमुख क्षेत्रों में से हैं, जहां तापमान में वृद्धि होने पर जैव-विविधता के नुकसान बढ़ने की आशंका है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इंडिया के महासचिव रवि सिंह का कहना है, 'हाल में चीतों के स्थानांतरण जैसी परियोजना वन्य प्रजातियों के संरक्षण का अच्छा उदाहरण है, और भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर तथा एक सींग वाले राइनो और शेरों के संरक्षण जैसी सफलताएं देखी हैं। इन प्रजातियों के संरक्षण का उस आवास क्षेत्र में रहने वाली अन्य सभी प्रजातियों पर प्रभाव पड़ता है।'

जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रकाशित द्विवार्षिक रिपोर्ट बताती है कि कैसे वन्यजीव निरंतर घटती जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दबाव झेल रहे हैं। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर निगरानी वाले वन्यजीव की आबादी में 1970 और 2018 के बीच 94 फीसदी की औसत गिरावट गिरावट देखी गई है। इसी अवधि के दौरान, अफ्रीका में निगरानी आबादी में 66 फीसदी की गिरावट आई, जबकि एशिया-प्रशांत की निगरानी आबादी में 55 फीसदी ह्रास दर्ज किया गया। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने पाया है कि मीठे पानी में रहने वाले जंतुओं की आबादी में सबसे अधिक गिरावट आई है-1970 और 2018 के बीच औसतन 83 फीसदी की गिरावट। आईयूसीएन रेड लिस्ट से पता चलता है कि साइकैड्स (बीज पौधों का एक प्राचीन समूह) सबसे अधिक खतरे वाली प्रजातियां हैं, जबकि कोरल रीफ सबसे तेजी से घट रहे हैं और उसके बाद उभयचर।

दुनिया भर में वन्यजीवों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण है, उनके प्राकृतिक आवासों, विशेषकर वनों का क्षरण और दोहन। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों में पौधों और जंतुओं की आक्रामक प्रजातियों का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे मूल वन्यजीवों को पर्याप्त आहार नहीं मिल पा रहा है और ऊपर से वे आक्रामक जंतुओं के शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बीमारी वन्यजीवों की आबादी घटाने वाले अन्य कारण हैं। अबाध गति से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भूमि-उपयोग में परिवर्तन भी प्रकृति के लिए बड़ा खतरा है।

जो प्राकृतिक परिवेश वन, जीव-जंतुओं के मूल निवास थे, उनमें से अधिकांश को कृषि भूमि, सड़कों, पर्यटक स्थलों और मानव आवासों के विकास हेतु अधिकृत कर लिया गया है। सबसे अनमोल संसाधन भूमि है और आर्थिक विकास उसके उपयोग का केंद्र-बिंदु बन गया है। अगर हम धरती के

तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में असमर्थ होते हैं, तो आशंका है कि आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन ही जैव-विविधता के विलोप का प्रमुख कारण होगा। उदाहरण के लिए, समुद्री जल के गर्म होने से लगभग 50 फीसदी कोरल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं।

रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया है कि स्थलीय कृषि, जलीय कृषि और तटीय विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रति वर्ष 0.13 फीसदी की दर से मैंग्रोव की कटाई जारी है। तूफान और तटीय कटाव जैसे प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ अति दोहन और प्रदूषण से कई मैंग्रोव विनष्ट हो जाते हैं। मैंग्रोव जैव-विविधता संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास हैं और तटीय समुदायों की अनेकानेक सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति मैंग्रोव से ही होती है। उदाहरण के लिए, 1985 के बाद से सुंदरवन मैंग्रोव का 137 किलोमीटर हिस्सा नष्ट हो गया है, जिससे वहां रहने वाले एक करोड़ लोगों में से कई के लिए भूमि और पारिस्थितिक सेवाएं कम हो गई हैं।

स्वच्छ और निर्मल धाराएं जीव-जंतुओं के आवास का प्राकृतिक स्रोत हैं। लेकिन केवल 37 फीसदी नदियां ही बची हैं, जो 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं और मुक्त बहती हैं। भारत में शेष नदियां मुक्त-प्रवाह की अवस्था में नहीं रह गई हैं। जब बहती नदी प्रदूषित हो जाती है और उसका प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है, तो उसके अंदर पनपने वाले जीव-जंतुओं का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया वह क्षेत्र है, जहां प्रजातियों के विलुप्तीकरण के खतरे ज्यादा हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तटों पर जलवायु परिवर्तन के उच्चतम प्रभाव की आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं, जिनका विशेष रूप से पक्षियों के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

प्रकृति की जैव-विविधता जीवित ग्रह पर जीवन की सततता, स्थायित्व और प्रफुल्लता का आधार है। वन्यजीव प्राकृतिक विविधता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। यदि वन्यजीवों की आबादी यों ही सिमटती रही, उनके पारिस्थितिक परिवेश यों ही लुटते-उजड़ते रहे, और जीव प्रजातियां यों ही विलुप्त होती रहीं, तो समझिए पारिस्थितिकी का तख्तापलट सन्निकट है। वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतिक परिवेशों की सुरक्षा व विस्तार हमारे सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं के केंद्र में हों, तभी हम अपने अक्षय विकास के पथ पर बढ़ सकेंगे।

समझता क्यों नहीं चीन

अवधेश कुमार

चीन पर पारंपरिक राजनीति फिर देश को निराश कर रही है। विपक्ष का काम सरकार से जवाब लेना है। क्या यह हर विषय और मुद्दे पर लागू हो सकता है?

चीनी सेना ने तवांग सेक्टर में 17 हजार फीट की ऊंचाई पर घुसपैठ की असभ्य कोशिश की। यह सच है। यह भी सच है कि हमारे जवानों ने उनको पीठ मोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसमें ऐसा क्या है जिस पर राजनीति में इतना बड़ा बवंडर खड़ा होना चाहिए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो बयान दिया वह मान्य होना चाहिए। बावजूद विपक्ष मान नहीं रहा है तो इसे कैसी राजनीति कहा जाए?

राज्य सभा और लोक सभा, दोनों में ज्यादातर विपक्षी दल हंगामा और बहिर्गमन कर रहे हैं। नेताओं के बयान ऐसे हैं मानो भारतीय सेना ने चीन के समक्ष समर्पण कर दिया हो। हालांकि वे कहते हैं कि हम सब सेना के साथ हैं। अगर सेना के साथ हैं तो आपको उनकी बहादुरी, उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी विश्वास होना चाहिए। कुछ नेता अलग-अलग नियमों के तहत चर्चा कराने पर अड़ गए। किंतु देश का ध्यान रखते हुए इस पर कब चर्चा हो, कैसे चर्चा हो और कितनी चर्चा हो इसके प्रति सदा सतर्क रहना आवश्यक है। क्या हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं को इसका भान नहीं है कि चीन से जुड़ी रक्षा नीति का खुलासा नहीं होना चाहिए?

अगर विपक्ष सरकार को मजबूर कर दे कि आप बताइए, चीन से आप कैसे निपट रहे हैं, और आगे कैसे निपट आएंगे तो होगा क्या? क्या दुनिया के किसी परिपक्व देश में सबसे बड़े दुश्मन के विरुद्ध इस तरह की राजनीति संभव है? बहुत कुछ कहा नहीं जाता लेकिन संकेत मिलता रहता है। क्या सरकार की ओर से इसका संकेत नहीं मिला है? इसका उत्तर है कि सरकार बिना घोषणा के बहुत कुछ संकेत दे रही है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में भारतीय वायु सेना ने अभ्यास शुरू कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दो दिवसीय युद्धाभ्यास में राफेल समेत अग्रिम पंक्ति के सभी लड़ाकू विमान शामिल हुए। हालांकि सेना ने कहा कि यह तवांग क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम से जुड़ा नहीं है।

बावजूद तनाव के बीच अभ्यास हुआ है तो इसका संदेश तो है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायु सेना के सभी अग्रिम अड्डे और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी अभ्यास में शामिल किए गए। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास राफेल के साथ-साथ सुखोई समेत कई तरह के युद्धक विमानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। चीनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ यूएवी ने भी क्षमता प्रदर्शित की। यह अभ्यास पूर्वी कमान के तहत हुआ जो असम, अरु णाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के हवाई अड्डे में किया गया। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा और कलाइकुंडा, असम के तेजपुर और झाबुआ और अरु णाचल प्रदेश की एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप से विमानों को उड़ान भरते देखा गया। सेना और वायु सेना ने अरु णाचल और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 2 सालों से उच्चस्तरीय संचालनात्मक तैयारियां बरकरार रखा है। पिछले सप्ताह भी अरु णाचल के तवांग सेक्टर में भारतीय वायु सेना ने एलएसी पर लड़ाकू विमान उड़ाए। यह सब क्या रंगमंच या फिल्म का प्रदर्शन है?

एक परिपक्व देश को इन सारे संकेतों को समझते हुए चीन जैसे दुश्मन देश के मामलों की संवेदनशीलता पर हंगामा और ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। यह भी देखिए कि चीन की ओर से कैसी प्रतिक्रिया आई है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि हमारे सैनिक तय नियम व मानकों के तहत निर्धारित सीमा पर गश्त लगा रहे थे और भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश भी जिन्हें विफल कर दिया गया। जरा सोचिए , भारत में इस बात को लेकर हंगामा है कि चीनी सैनिकों ने हमारे यहां घुसपैठ की कोशिश कैसे कर दी? सच यह है कि चीनी सेना समय-समय पर ऐसी हरकतें करती रहती हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि घटना 9 दिसम्बर को रात में हुई और सरकार ने इसे छिपाए रखा। घटना अवश्य रात में हुई लेकिन उसके बाद दो दिनों बाद फ्लैग मीटिंग हुई और उसमें बातचीत पूरी होने के बाद यह बाहर आया। दूसरे, यह चीन के रवैये को देखते हुए इतनी बड़ी घटना न थी और न ही अनअपेक्षित था। उनकी सेनाएं घुसने की कोशिश करती हैं, हमारी सेना रोकती हैं, जरूरत पड़ने पर उनको पीटती भी हैं। इसी हंगामे के बीच अक्टूबर, 2021 का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें हमारी सेना चीन के सैनिकों को लाठियों से पीटकर भगा रही है। वास्तव में 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने जिस बर्बरता और उद्दंडता के साथ हमला किया उसके बाद पूरी सीमा क्षेत्र में उसी ढंग की तैयारी भारतीय सेना ने की। वह नुकीले कील लगे हुए डंडे, रड , ईट, पत्थर आदि लेकर हमला करने आए थे।

तो उनका जवाब कैसे दिया जाए इसके लिए पूरी तैयारी है और चीन की सेना की हरकतों को जवाब मिल रहा है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जो कहेगी कि चीन के सैनिक हमारी ओर घुसपैठ करते हैं तो आप उनका मुंहतोड़ जवाब नहीं दीजिए। तो फिर हंगामे का मकसद क्या हो सकता है? चीन का विवाद केवल भारत के साथ ही नहीं है। रूस को छोड़कर सारे पड़ोसियों के साथ उसके सीमा विवाद हैं। दक्षिण चीन सागर से उसका कोई लेना-देना नहीं लेकिन वहां बड़े क्षेत्र में नौसेना-वायु सेना आदि के साथ वह अड़ा हुआ है। जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई आदि सभी के साथ उसका तनाव चल रहा है।

दुनिया के प्रमुख देशों के लिए भी यह बड़ा प्रश्न है कि चीन की सैन्य और भौगोलिक महत्त्वाकांक्षाओं, विस्तारवादी नीतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए? भारत जैसे देश के करीब 43 हजार किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इन मामले में ज्यादा संतुलन के साथ सामने आना चाहिए। दुर्भाग्य से इसके उलट हो रहा है। वैसे भी जब तनाव का दौर हो तो देश के अंदर शांति और एकता दिखनी चाहिए। कल्पना करिए, कल चीन कुछ सैनिकों को किसी क्षेत्र में जबरन घुसाने की कोशिश कर अपने अनुसार वीडियो बनाकर रिलीज कर दे तो भारत के राजनेता आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। फिर तो चीन को हमें लड़ाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।

कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी विभिन्न कक्षाओं में दाखिला और भाग ले रहे हैं जो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पैटर्न विभिन्न आयु समूहों में देखा गया है जिसके कारण भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है।

बच्चों को घर बैठे खेल-खेल में सिखाएं गणित के गुण

कोरोना वायरस महामारी के बाद कई छात्र काफी मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए कई छात्र नए-नए हुनर सीख रहे हैं। ऐसे में भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग काफी बढ़ गई है। माता-पिता अपने बच्चों को नए कौशल सिखाने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को गणित और सांख्यिकी गणना सिखाना चाहते हैं तो अबेकस ट्रेनिंग क्लास की मदद से आप अपने बच्चों को खेल में गणित पढ़ा सकते हैं।

कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी विभिन्न कक्षाओं में दाखिला और भाग ले रहे हैं जो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पैटर्न विभिन्न आयु समूहों में देखा गया है जिसके कारण भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है। माता-पिता अलग-अलग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसके माध्यम से उनके बच्चों को रचनात्मक सीखने के माहौल में पाला जा सकता है। गणित और संख्या कुछ बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन जब गणना की बात आती है तो स्कूल और कॉलेज के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा कुछ हद तक संघर्ष करता है। अबेकस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सदियों से मौजूद है और इसे अंकगणितीय कौशल और संख्यात्मक प्रवाह को विकसित करने के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छे उपकरणों में से एक माना जाता है।

अबेकस टूल का उपयोग गणितीय कार्यों जैसे जोड़, घटाव, गुणा, वर्ग या घनमूल को करने के लिए किया जाता है। अबेकस का उपयोग दशमलव अंक, ऋणात्मक संख्या और बहुत कुछ गिनने के लिए भी किया जा सकता है। अपने गणना कौशल में सुधार के अलावा, अबेकस सीखने से बच्चे के समग्र विकास में मदद मिल सकती है। अबेकस सीखने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं :

- कैलकुलेशन की गति और सटीकता में सुधार करता है
- विश्लेषणात्मक कौशल और तार्किक रीजनिंग का निर्माण करता है
- गणित में रुचि पैदा करता है
- एकाग्रता और अवलोकन शक्ति को बढ़ाता है
- मेमोरी में सुधार करता है
- आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बनाता है

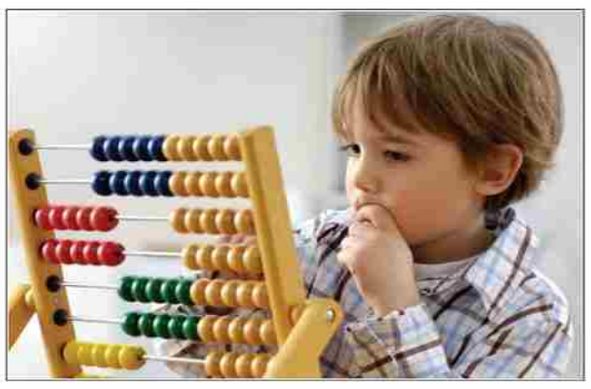

यहां भारत में पांच ऐसे प्लेटफार्मों के बारे में बताया गया है जो 100 प्रतिशत डिजिटल एबेकस प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और युवाओं को भविष्य के रोल मॉडल बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

ब्रिटिश यूथ इंटरनेशनल कॉलेज

यूके स्थित प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन अबेकस शिक्षण मंच लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। उनके मंच में पूरी तरह कार्यात्मक वर्चुअल अबेकस है जो बच्चों के समग्र मानसिक विकास के लिए इंटरैक्टिव प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली अबेकस शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। ये ऑनलाइन कक्षाएं चरण-दर-चरण अप्रोच प्रदान करती हैं जिसका उद्देश्य छात्रों को अबेकस को ध्यान में रखकर मार्गदर्शन करना और कैलकुलेटर की तुलना में तेजी से संख्या की गणना करना है। शिक्षक प्रत्येक छात्र को गहन शिक्षण प्रदान करते हैं। वे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव जोड़, दशमलव घटाव, दशमलव गुणा और दशमलव भाग को कवर करते हैं। वे एकमात्र अबेकस कंपनी हैं जो दशमलव आधारित गणना प्रदान करती हैं।

उडेमी

उदमी अबेकस कोर्स का उद्देश्य आपकी गणना, क्षमता, संख्या बोध और मानसिक अंकगणित को बेहतर बनाने में मदद करके मस्तिष्क का विकास करना है। यह पाठ्यक्रम मल्टीमीडिया और एनिमेशन के जरिये आपको सिखाएगा कि अबेकस पर सही और तेज बुनियादी गणित संचालन कैसे करें। इन अबेकस ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करके बच्चे अबेकस पर संख्याएं रखने, हल करने और जोड़ और घटाव को समझने में सक्षम होंगे।

अबेकस सुपरमैथ्स

'सुपरमैथ्स' छात्रों को अबेकस टूल का उपयोग करने के लिए एक दोस्ताना और इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है। उनकी कक्षाएं आपको ऑनलाइन वर्कशीट पर काम करके मानसिक सिद्धांत अवधारणाओं को अभ्यास में लाने की अनुमति देती हैं। यह कोर्स दो ट्रैक में आता है, जूनियर और सीनियर। पहले ट्रैक में 11 स्तर होते हैं जबकि दूसरे वरिष्ठ ट्रैक में 8 स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर के अंत में एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके बाद छात्र को अगले स्तर पर पदोन्नत किया जाता है। वे प्रशिक्षक के नेतृत्व में आवेदन आधारित वीडियो कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं।

अबेकस मास्टर

अबेकस मास्टर ने अबेकस को अधिक रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए अनूठी विशेषताओं के साथ एक व्यापक शिक्षण मंच बनाया है। यह ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 5-12 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों को अबेकस प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें आठ स्तर शामिल होते हैं जो बुनियादी से लेकर उन्नत अबेकस गणनाओं तक सभी विषयों को कवर करते हैं। छात्र इस पाठ्यक्रम को अपनी गति के हिसाब से ले सकते हैं; हालाँकि, पोर्टल पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए प्रत्येक स्तर पर कम से कम दो महीने बिताने का सुझाव देता है। उनकी कक्षाएं एनिमेशन, अंजान वीडियो और प्रैक्टिस वर्कशीट की मदद से दी जाती हैं।

स्मार्ट किड अबेकस

स्मार्ट किड की 'अबेकस फ्रेंचाइजी' बच्चों के लिए अबेकस ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करती है। ये कक्षाएं सप्ताह में एक बार 45 मिनट के लिए आयोजित की जाती हैं। समय में कोई पाबन्दी नहीं है और छात्र कई प्रकार के पाठ्यक्रमों में से चुन सकते हैं। यह आठ स्तरीय पाठ्यक्रम है जिसमें 5 बुनियादी और 3 अग्रिम स्तर हैं। पाठ्यक्रम 4-14 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये पाठ्यक्रम कौशल के विकास के साथ-साथ संपूर्ण मस्तिष्क विकास को बढ़ावा देते हैं।

फ्लाइट में यात्रियों की मेहमान नवाजी कर कमाएं हजारों

केबिन क्रू का मतलब होता है केबिन के कर्मचारी। किसी भी फ्लाइट में जहाँ यात्री बैठते हैं, उसे केबिन कहते हैं। फ्लाइट में यात्रियों की सेवा और सुरक्षा के लिए जो टीम होती है, उसे केबिन क्रू कहते हैं। केबिन क्रू की जिम्मेदारी फ्लाइट में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और यात्रियों को फ्लाइट के नियम समझाना होता है। बहुत से लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि केबिन क्रू कैसे बनें। आज के इस लेख में हम आपको केबिन क्रू बनने के लिए जरूरी योग्यता, प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देंगे

केबिन क्रू की जिम्मेदारी फ्लाइट में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और यात्रियों को फ्लाइट के नियम समझाना होता है। बहुत से लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि केबिन क्रू कैसे बनें।

योग्यता

- उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की हो तो आप केबिन क्रू की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक की ऊंचाई 157 से 170 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 17 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

जरूरी कौशल

- केबिन क्रू बनने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए।
- केबिन क्रू बनने के लिए दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने का ढंग होना चाहिए।
- आपके शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए।
- आपकी अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
- केबिन क्रू बनने के लिए अच्छी पर्सनालिटी और गुड लुक्स भी जरुरी होते हैं।

कोर्सेज

- डिप्लोमा इन केबिन क्रू एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड ट्रेवल मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एयरलाइन केबिन क्रू
- सर्टिफिकेट कोर्स इन एयर हॉस्टेस

केबिन क्रू कैसे बनें

- एयरलाइन कंपनियां समय-समय पर केबिन क्रू की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती हैं।
- केबिन क्रू का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
- इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आवेदक की शारीरिक जाँच और मेडिकल टेस्ट होता है।
- मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है।
- इन सभी टेस्ट्स को पास करने वाले उम्मीदवारों का चयन केबिन क्रू के लिए होता है।

सैलरी

शुरुआत में बतौर केबिन क्रू आपकी सैलरी प्रतिमाह 30,000 रूपये से 50,000 रूपये तक हो सकती है। हालांकि, समय के साथ अनुभव होने पर सैलरी बढ़कर 70 हजार रूपये से 1 लाख रूपये प्रतिमाह तक हो सकती है।

वैकल्पिक चिकित्सा में कॅरियर बनाना चाहते हैं तो चुनें मैग्नेटिक थेरेपी

एक मैग्नेटो चिकित्सक को मैग्नेटोमीटर के सही उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो एक चुंबक के ध्रुवों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको चुंबकीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की भी सही जानकारी होनी चाहिए।

मैग्नेटिक थेरेपी, जिसे मैग्नेट थेरेपी या मैग्नो थेरेपी भी कहा जाता है, वास्तव में एक वैकल्पिक चिकित्सा उपचार है, जिसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद सिंपल, इफेक्टिव, सुरक्षित व पूरी तरह से दर्दरहित प्राकृतिक उपचार है। चुंबकीय चिकित्सा को एक विज्ञान के साथ-साथ एक कला के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के विभिन्न अंगों, रोगों को जानने के साथ-साथ व मैग्नेट के उचित उपयोग को जानना भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान में, चुंबकीय चिकित्सा एक्यूपंक्चर के समान है। वहीं कला में, इसमें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न आकारों और शक्तियों के मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद डिफरेंट चिकित्सा थेरेपी है। तो चलिए जानते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे बनाएं कॅरियर-

स्किल्स

एक मैग्नेटो चिकित्सक को मैग्नेटोमीटर के सही उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो एक चुंबक के ध्रुवों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको चुंबकीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की भी सही जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मानव शरीर व उसके महत्वपूर्ण अंगों की रचना व उसके विज्ञान के बारे में भी पता होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता

भारत में केवल कुछ ही संस्थान मैग्नेट थैरेपी पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। मैग्नेट थेरेपी में सर्टिफिकिट, डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10, 2 है और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक होना आवश्यक है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 वर्ष की है और स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का है। कुछ संस्थान शार्ट टर्म डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा कोर्स भी करवाते हैं, जिनकी अवधि एक से तीन महीने की होती है। एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट प्राइवेट व पब्लिक हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या वैकल्पिक उपचार चिकित्सा केन्द्रों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक थेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह उपचार के लिए मैग्नेटिक ज्वैलरी, ब्रेसलेट व अन्य उत्पादों को भी बेच सकते हैं। एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट की आय असीमित है। उनकी आय उनके चिकित्सीय कौशल पर निर्भर करती है। सेल्फ इंपलायड मैग्नेटिक थेरेपिस्ट घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। उनका एक सेशन करीबन 20 से 30 मिनट का होता है।

प्रमुख संस्थान

- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
- एक्यूप्रेशर रिसर्च, टेनिंग व टीटमेंट इंस्टीट्यूट, जोधपुर
- ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल, लुधियाना
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे
- कॉलेज ऑफ क्लिनकिल मैग्नेटोलॉजी और प्राण हीलिंग कॉलेज, त्रिशूर
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, बैंगलोर
- महेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, जयपुर

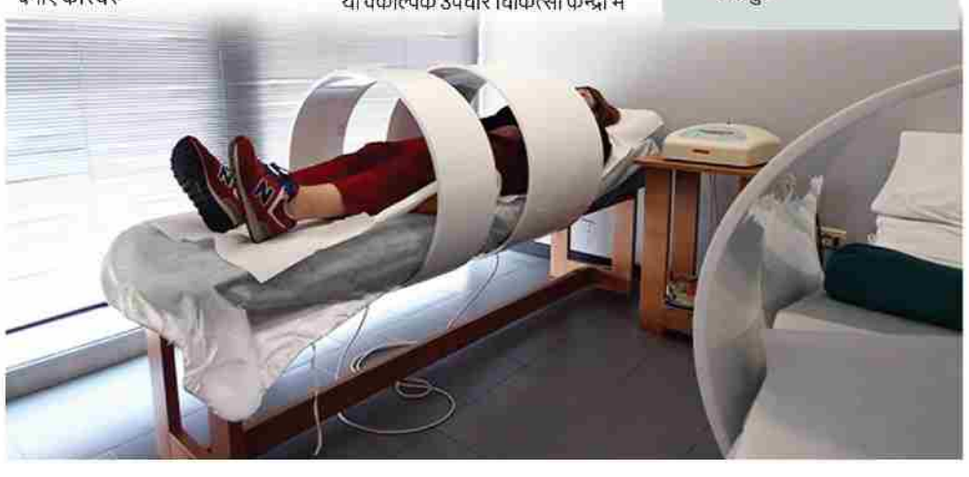

एक्वापॉनिक्स फार्मिंग में है बेहतर भविष्य

एक्वापोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक्वाकल्चर जिसमें मछली पालन होता है और दूसरा हाइड्रोपोनिक जिसमें पानी पर खेती होती है। एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ और पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है।

आज के समय में एग्रीटेक स्टार्टअप बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। एक्वापोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक्वाकल्चर जिसमें मछली पालन होता है और दूसरा हाइड्रोपोनिक जिसमें पानी पर खेती होती है। एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ और पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है जबकि इसमें पौधे दोगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं। एक्वापॉनिक्स में एक फिश टैंक में मछली पालन किया जाता है और दूसरी तरफ पानी पर हाइड्रोपोनिक खेती का सिस्टम बनाया जाता है। फिश टैंक में मछलियां फीड खाने के बाद करीब 70 फीसदी तक मल निकालती हैं जिसमें अमोनिया होता है। इसके बाद फिश टैंक से अमोनिया वाले पानी को हाइड्रोपोनिक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया इसे नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। यह पौधों के विकास के लिए बहुत ही अहम होता है। इसके बाद पानी को फिर से प्यूरिफाई किया जाता है और दोबारा मछलियों के टैंक में डाला जाता है। इस तरह एक ही पानी बार-बार इस्तेमाल होता रहता है और पानी की बचत होती है।

एक्वापोनिक फार्मिंग सेटअप तैयार करने में कितनी लागत आएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बड़ा सेटअप तैयार करना चाहते हैं या छोटा। उदाहरण के लिए अगर आप एक एकड़ जमीन पर एक्वापोनिक फार्मिंग करते हैं तो आपका करीब 3 करोड़ रूपए तक का खर्चा आ सकता है। इसके साथ ही अगर आप मुनाफा चाहते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीजें इस्तेमाल करनी होंगी। एक्वापोनिक खेती से हुई पैदावार पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है इसलिए आप इसके लिए सामान्य की तुलना में दो से तीन गुना कीमत कमा सकते हैं। हालाँकि, आपको पैदावार से पहले ही उसे बेचने की तैयारी कर लेनी होगी वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप बड़े-बड़े रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट और फाइव स्टार होटलों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।

सिंगापुर का ग्लोबल स्कूल फाउंडेशन भारत के शिक्षा क्षेत्र में 55 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा

सिंगापुर। सिंगापुर स्थित भारतीय मूल के ग्लोबल स्कूल फाउंडेशन (जीएसएफ) ने भारत के स्कूली शिक्षा क्षेत्र में 2026 तक 55 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। जीएसएफ की पहले से ही बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और नोएडा में उपस्थिति है। कोविड-महामारी के बाद स्थानीय समुदायों द्वारा दाखिले के लिए मांग में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। परिवारों के एक से दूसरे शहरजाने और दूसरे देशों से स्वदेश लौटने के बीच मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। जीएसएफ के कार्यकारी चेयरमैन और सह-संस्थापक अतुल तेमुनिकर ने बयान में कहा, ''यह जरूरी है कि जीएसएफ अपने नेटवर्क में ऐसे छात्रों को बिना किसी व्यवधान के गारंटी के साथ प्रवेश दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।'' उन्होंने कहा, ''जीएसएफ की वैश्विक विस्तार की योजना के तहत भारत को अपने रणनीतिक बाजारों में से एक बनाने की है। इसके अलावा वर्ष 2026 तक भारत के स्कूल शिक्षा क्षेत्र में 55 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना है।

साझेदारी को और गहन बनाने के लिए चीन और रूस की नौसेनाएं करेंगी युद्धाभ्यास

बीजिंग । चीन का कहना है कि बुधवार को रूसी नौसेना के साथ होने वाले दोनों देशों के अभ्यास का उद्देश्य सहयोग को और गहनता प्रदान करना है जिनके अनौपचारिक पश्चिम विरोधी गठबंधन ने यूक्रेन पर मास्को के हमले के बाद ताकत हासिल की है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तहत चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड द्वारा सोमवार को पोस्ट किए गए एक संक्षिप्त नोटिस के अनुसार अभ्यास अगले मंगलवार तक शंघाई के दक्षिण में झेजियांग प्रांत के तट पर चलेगा। नोटिस में कहा गया है कि यह संयुक्त अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों का मिलकर जवाब देने के लिए दोनों पक्षों के दृढ़ संकल्प और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित है और चीन-रूस में नए युग की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वारयाग मिसाइल क्रूजर मार्शल शापोशनिकोव विध्वंसक और रूस के प्रशांत बेड़े के दो जंगी जहाज युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। मंत्रालय ने कहा कि चीनी नौसेना ने अभ्यास के लिए कई युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को तैनात करने की योजना बनाई है। दोनों पक्षों के विमान भी इसमें भाग लेंगे। चीनी पक्ष की तरफ से यह फिलहाल नहीं बताया गया है कि उसकी तरफ से युदाभ्यास में कौन सी इकाइयां शामिल होंगी। दशकों के आपसी अविश्वास से आगे बढ़ते हुए चीन और रूस ने अमेरिका के नेतृत्व वाली उदार पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करने के लिए विदेश नीतियों में तालमेल के हिस्से के रूप में इस तरह की कवायद तेज कर दी है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना करने या यहां तक कि इसका उल्लेख करने से भी इनकार कर दिया। उसने हालांकि मास्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों की निंदा की है और वाशिंगटन और नाटो पर व्लादिमीर पुतिन को कार्रवाई के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

किम की बहन ने खुफिया उपग्रह पर संदेह वाले आकलन को दुर्भावनाप्रेरित व कुत्तों के भौंकने के बराबर बताया

सियोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो जोंग ने उस आकलन को दुर्भावनापूर्ण अपमान और कुत्तों के भौंकने के बराबर बताते हुए खारिज कर दिया जिसमें देश के जासूसी उपग्रह व अन्य सैन्य क्षमताओं पर संदेह व्यक्त किया गया था। उत्तर कोरिया ने कहा था कि उसने अपने पहले खुफिया उपग्रह के निर्माण के लिए रविवार को महत्वपूर्ण अंतिम चरण के परीक्षण किए। उत्तर कोरिया की आधिकारिक मीडिया ने दो 'कम रेजॉल्यूशन' वाली श्वेत-श्याम तस्वीरें भी जारी की थीं जिसमें अंतरिक्ष से दक्षिण कोरियाई राजधानी और सियोल के पश्चिम में स्थित शहर इंचियोन नजर आ रहा है। सरकारी मीडिया ने वर्कर्स पार्टी की वरिष्ठ अधिकारी किम यो जोंग के हवाले से एक खबर में कहा क्या उन्हें नहीं लगता कि उनका आकलन बेहद अनुचित व लापरवाही भरा है। उन्होंने हमारे समाचार पत्र द्वारा जारी केवल दो तस्वीरों के आधार पर हमारे उपग्रह की विकास क्षमताओं और उससे जुड़ी तैयारियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने उपग्रह की तस्वीरों पर दक्षिण कोरिया के विशेषज्ञों की टिप्पणी को बकवास दुर्भावना से किया जाने वाले अपमान और कुत्तों के भौंकने के बराबर बताया। किम यो जोंग ने कहा कि उपग्रह के परीक्षण के दौरान एक आम कैमरे का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि एक बार के परीक्षण के लिए महंगे उच्च-रेजॉल्यूशन वाले कैमरे का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के रूप में दो पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। किम यो जोंग ने कहा अगर हमें एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का प्रक्षेपण करना होगा तो हम करेंगे। हम लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण को छुपाने के लिए उपग्रह का इस्तेमाल नहीं करते जैसा कि दक्षिण कोरियाई आम राय को प्रभावित करने के लिए दावा कर रहे है। उन्होंने दक्षिण कोरियाई सरकार के उस आकलन को भी खारिज कर दिया कि उत्तर कोरिया के पास अमेरिका की मुख्य भूमि को निशाना बनाने में सक्षम आईसीबीएम का इस्तेमाल करने के लिए अब भी पर्याप्त प्रौद्योगिकी नहीं है। किम यो जोंग ने कहा मुझे लगता है कि उनके लिए बेहतर यही है कि वह बकवास करना बंद करें सावधानी बरतें और कुछ भी करने से पहले दो बार उस पर विचार करें। गौरतलब है कि एक खुफिया उपग्रह का विकास उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है।

समिति ने ट्रंप के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने का किया आग्रह

– समिति ने पूर्व राष्ट्रपति की जवाबदेही तय करने का आग्रह भी किया

वाशिंगटन । अमेरिकी संसद परिसर (कैपिटल हिल) में 2021 में हुए हमले की जांच कर रही 'हाउस जनवरी 6 समिति' ने न्याय मंत्रालय से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने का आग्रह किया। समिति ने पूर्व राष्ट्रपति की जवाबदेही तय करने का आग्रह भी किया। कांग्रेस के इतिहास में अभी तक की सबसे गहन जांच के बाद समिति ने ट्रंप और उनके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों की सिफारिश की। समिति में सात डेमोक्रेट और दो रिपब्लिकन सांसद शामिल हैं। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट का एक लंबा साराश भी जारी किया जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि ट्रंप ने चुनाव के नतीजे पलटने के लिए व्यापक स्तर पर साजिश रची। गौरतलब है कि ट्रंप ने तीन नवंबर 2020 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। ट्रंप के इन आरोपों के बीच उनके समर्थकों ने छह जनवरी को संसद भवन परिसर में कथित तौर पर हिंसा की थी। समिति ने जिन चार आरोपों के तहत ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने का आग्रह किया है वे आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालना अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचना झूठे बयान देना और किसी विद्रोह को भड़काना या उसमें मदद करना है। हालांकि समिति के सुझावों को लेकर न्याय मंत्रालय पर कानूनी कार्यवाही का कोई दबाव नहीं है क्योंकि संघीय अभियोजक पहले से ही अपनी जांच कर रहे हैं और वे ही ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर अंतिम फैसला लेंगे।

दास व्यापार में नीदरलैंड की भूमिका के लिए डच नेता ने मांगी माफी

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने गुलामी और दास व्यापार में नीदरलैंड की ऐतिहासिक भूमिका के लिए अपनी सरकार की ओर से सोमवार को माफी मांगी। गुलामी और दास व्यापार को लेकर नीदरलैंड की ओर से लंबे समय से प्रतीक्षित बयान में विलंब करने की मांग के बावजूद मार्क रुटे ने यह बयान दिया। रुटे ने 20 मिनट के अपने भाषण में कहा, ''आज मैं माफी मांगता हूं।'' राष्ट्रीय अभिलेखागार में आमंत्रित दर्शकों की ओर से उनका मौन स्वागत किया गया। रुटे ने माफी के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई। हालांकि कुछ कार्यकर्ता समूहों ने देश में दासता के उन्मूलन की अगले साल एक जुलाई को आने वाली सालगिरह तक इंतजार करने का उनसे आग्रह किया था। प्रधानमंत्री के भाषण को रोकने के लिए कुछ लोग पिछले सप्ताह अदालत भी गए थे, लेकिन वे इसमें असफल रहे थे।

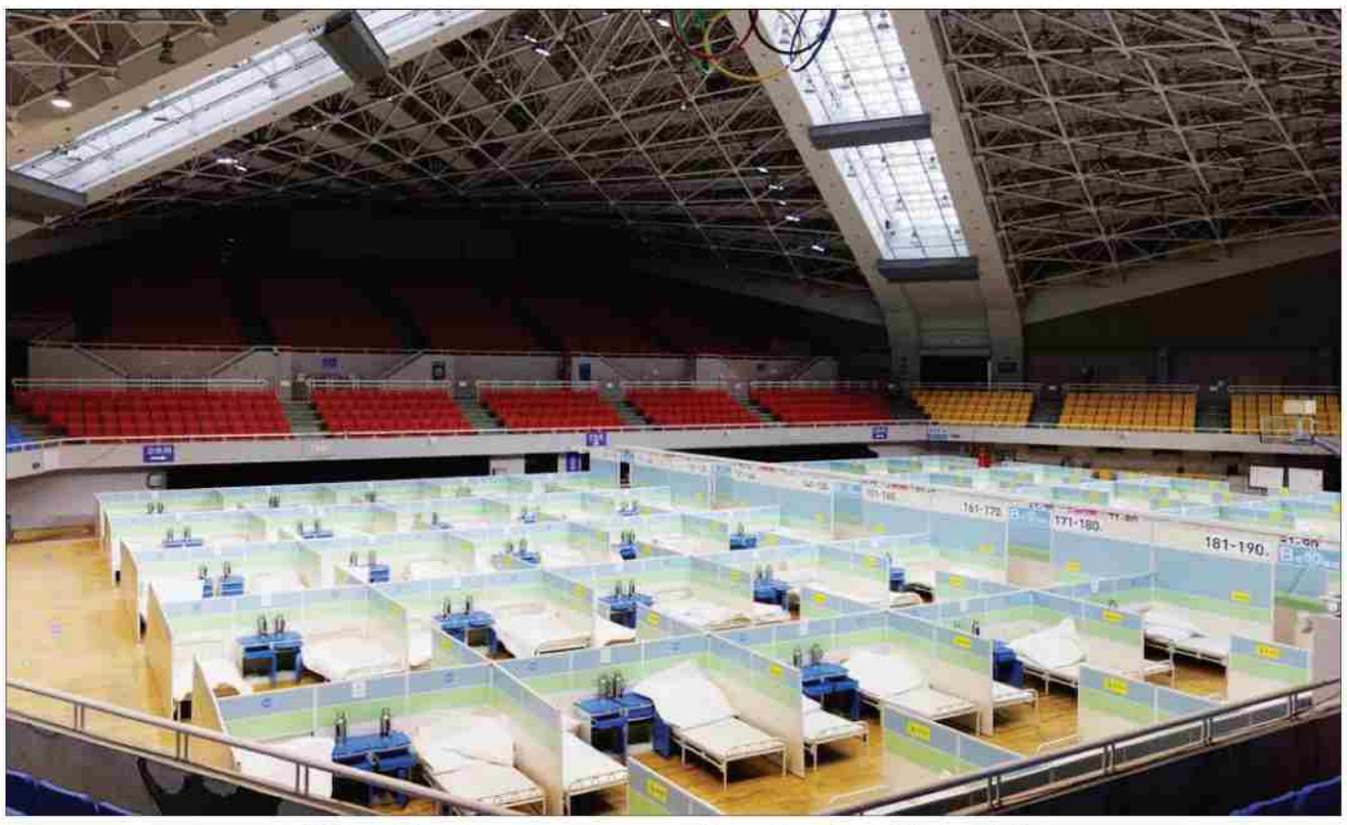

बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद एक फीवर क्लीनिक में मरीजों के लिए रखे बेड।

चीन ने बिना किसी तैयारी दे दी ढील एक आदमी 16 लोगों को कर रहा कोरोना से संक्रमित

बीजिंग । चीन ने जीरो कोविड नीति में बिना किसी तैयारी के ढील दे दी है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि चीन के अस्पतालों में बेड खाली नहीं बचे हैं। छोटे-छोटे क्लीनिक पर भी भीड़ बढ़ गई है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। संक्रमण फैलने की रफ्तार इतनी तेज है कि 1 शख्स 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है। विशेषज्ञ इससे बचने के लिए कोविड गाइडलाइन्स मानने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में कोरोना वायरस के कारण मार्च तक 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। चीन में दी गई ढील के बाद कोरोना बड़े शहरों से ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया है जिसके बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस बीच सोमवार को दक्षिण-पश्चिमी चीन में चोंगकिंग में प्रशासन ने अजीबोगरीब तरीके से हल्के कोरोना लक्षण या बिना लक्षण वाले मरीजों को काम करने को कहा। इससे पहले पूर्वी प्रांत झेजियांग ने कहा था कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज जरूरत पड़ने पर काम पर लौट सकते हैं। कई कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी भी काम पर लौट आए हैं। चीन कोरोना वायरस के मामलों को छिपा रहा है। अनिवार्य कोरोना टेस्टिंग खत्म करने के बाद चीन ने संक्रमितों का डेटा जारी करना बंद कर दिया है जिसके कारण सही आंकड़े नहीं पता। अधिकारियों का कहना है कि बिना टेस्टिंग के असिंप्टोमैटिक मरीजों का पता नहीं लगाया जा सकता इसलिए डेटा जारी नहीं किया जा रहा।

इमरान खान ने कहा कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता था

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध सुधारना चाहते थे, लेकिन कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना इसमें 'बाधक' बन गया। क्रिकेटर से नेता बने 70 वर्षीय खान ने यह भी कहा कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत के साथ बेहतर संबंध रखने को लेकर और भी अधिक झुकाव था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान ने कहा, ''मैं अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता था, लेकिन आरएसएस की विचारधारा और (जम्मू कश्मीर के) विशेष दर्जे को खत्म करना इसमें बाधक बन गया।''

खान ने यह बात यहां जमां पार्क स्थित अपने आवास पर विदेशी पत्रकारों के एक समूह से बातचीत के दौरान कही। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद उनकी सरकार ने बातचीत पर जोर नहीं दिया। खान ने कहा, ''हम चाहते हैं कि भारत पहले अपने फैसले को पलटे और शांति वार्ता करे।'' प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने खान से पूछा कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत के प्रति विदेश नीति कौन निर्धारित कर रहा था, वह या फिर जनरल बाजवा, इस पर उन्होंने जवाब दिया, ''मैं बॉस था...मैं विदेश नीति निर्धारित कर रहा था। हालांकि, जाने दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जनरल बाजवा भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के इच्छुक थे।''

खान ने हाल में कहा था कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके पास शक्ति नहीं थी, क्योंकि जनरल बाजवा वह शख्स थे, जो निर्णय ले रहे थे। यह याद दिलाने पर कि उन्होंने भारत में चुनाव से पहले इच्छा व्यक्त की थी कि नरेंद्र मोदी जीतें क्योंकि वह कश्मीर मुद्दे को हल करेंगे, खान ने कहा, ''मुझे अभी भी विश्वास है कि दक्षिणपंथी पार्टी का नेता ही संघर्ष को हल कर सकता है। मोदी दक्षिणपंथी पार्टी से हैं, इसलिए मैं चाहता था कि वह सत्ता में लौटें और कश्मीर मुद्दे को हल करें।

डीएसआई से प्रकृति संरक्षण के लिए धन मुहैया कराया जाएगा इससे जैव विविधता के संरक्षण में मिलेगी मदद

मांट्रियल (एजेंसी)। कोप-15 सम्मेलन में जैवविविधता की रक्षा के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते के तौर पर अपनाए गए 'डिजीटल सिक्वेंस इंफोर्मेशन' (डीएसआई) से प्रकृति के संरक्षण के लिए भारत जैसे देशों को धन मुहैया कराया जाएगा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक (सीओपी15) चल रही है। जैव विविधता से संबंधित नागोया प्रोटोकॉल के जरिए संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता सम्मेलन का मकसद उपयोगकर्ताओं (कॉरपोरेट संस्थानों) तथा विकासशील देशों में इन संसाधनों का संरक्षण कर रहे स्वदेशी समुदाय तथा किसानों के बीच आनुवंशिक संसाधनों से पैदा हुए फायदों को वितरित करना है। अब डीएसआई तकनीक से कंपनियां संसाधनों को हासिल करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग के जरिए आनुवंशिक संसाधनों के न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस का इस्तेमाल कर सकती हैं। सीओपी15 में विकासशील देशों ने कहा है कि डीएसआई से मिलने वाले फायदों को समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। डीएसआई का उपयोग कुछ अंतरराष्ट्रीय नीति मंचों के संदर्भ में किया जाता है विशेष रूप से जैविक विविधता पर संधि आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त डेटा को संदर्भित करने के लिए। राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) के सचिव जस्टिन मोहन ने कहा देशों ने डीएसआई को संसाधनों तक पहुंचने और फायदे साझा करने के तंत्र में लाने पर स्वीकृति दी थी। विभिन्न देशों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर एक कार्यकारी समूह इन फायदों को साझा करने के तौर-तरीकों पर काम करेगा और तुर्किये में अगले सीओपी में इन सिफारिशों को अपनाने की उम्मीद है।

उत्तर कोरिया ने जापान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी

सियोल (एजेंसी)। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को जापान के खिलाफ 'सख्त और निर्णायक सैन्य कार्रवाई' करने की धमकी दी। साथ ही उसने जापान को एक आक्रामक सैन्य शक्ति में बदलने के प्रयास के रूप में टोक्यो के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपनाने की भी आलोचना की। उत्तर कोरिया का यह बयान जापान द्वारा सुरक्षा रणनीति की घोषणा के चार दिन बाद आया है। जापान ने घोषणा में चीन और उत्तर कोरिया की ओर से आने वाले खतरों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के लिए 'जवाबी हमला' करने की क्षमता को बढ़ाने और अपने सैन्य खर्च को दोगुना करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था।

उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जवाबी हमले की क्षमता हासिल करने के लिए जापान के प्रयास का आत्मरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन यह 'अन्य देशों के इलाकों पर हमले की एहतियाती क्षमता' हासिल करने का स्पष्ट प्रयास है। सरकारी मीडिया में मंत्रालय के एक अज्ञात प्रवक्ता के हवाले से दिए बयान में कहा गया, 'जापान का अपनी गलत मंशाओं को पूरा करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास, आत्मरक्षा के अधिकारों की आड़ में सैन्य आक्रमण की क्षमता को उचित नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसे बर्दाश्त किया जा सकता है।'

बयान में अमेरिका पर जापानी सैन्य महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने और बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति को कम करने का आरोप लगाया गया। बयान में कहा गया है कि इस तरह के कथित अमेरिकी कदम उत्तर कोरिया को देश पर हमला करने के दुश्मन के प्रयासों को विफल करने के लिए नए रणनीतिक हथियार विकसित करने की हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

बयान में कहा गया है कि उत्तर कोरिया यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह जापानी सुरक्षा रणनीति के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा की जटिलता के मद्देनजर अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए 'साहसिक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई' कर सकता है। बयान में कहा गया है, 'हमारा देश यह दिखाने के लिए कार्रवाई करना जारी रखेगा कि हम जापान के अन्यायपूर्ण, गलत मंशा वाले प्रयास से कितना चिंतित और नाराज हैं।

बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत-पाक के बीच बढ़ी तकरार, अब अमेरिका का आया यह रिएक्शन

सयोल (एजेंसी)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसके बाद से भारत के नेताओं ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान और वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का विरोध किया था। इतना ही नहीं, राजनयिक स्तर पर भी इस विरोध को दर्ज कराया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की चौतरफा आलोचना भी होती दिखाई दी। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी और बढ़ गई। इन सब के बीच अब अमेरिका का भी रिएक्शन आ गया। अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे लिए दोनों देश अच्छे साझेदार हैं और हम नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच किसी तरह का वाकयुद्ध हो। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने मर्यादाओं की सभी हदों को लांघते हुए पीएम मोदी पर निजी हमला किया था और उन्हें गुजरात का कसाई कहा था।

इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से

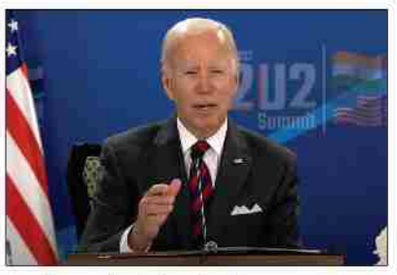

आपत्ति जताई गई थी। इसे पाकिस्तान का असभ्य बयान भी कहा गया था। इन सबके बीच अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उनसे बिलावल भुट्टो के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई। इसके जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी भारत के साथ वैश्विक सामरिक साझेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि संबंधों का मतलब किसी एक का फायदा और दूसरे का नुकसान नहीं है। हम इन्हें एक दूसरे से जोड़कर भी नहीं देखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों देश हमारे साझा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

इसके साथ ही नेड प्राइस ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मतभेद हैं जिन्हें निश्चित तौर पर दूर करने की जरूरत है। अमेरिका एक साझेदार के रूप में दोनों की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने भारत के साथ अपनी वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूत किया है, हमारा ऐसा रिश्ता भी है जिसमें हम एक-दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं। हमारे बीच असहमति या चिंता हो सकती है, हम उनसे ऐसे ही बात करते हैं जैसे कि हम अपने पाकिस्तानी मित्रों से करते हैं।'' एक अन्य सवाल के जवाब में प्राइस ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि 'यह युद्ध का युग नहीं है' तो दुनियाभर के देशों ने इस बयान का स्वागत किया था।

यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर किए गए ड्रोन हमले, पुतिन बेलारूस रवाना होंगे

कीव (एजेंसी)। यूक्रेन की राजधानी कीव में सोमवार तड़के ड्रोन द्वारा फिर से कई हमले किए गए। इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहयोगी देश बेलारूस का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 10 महीने पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए बेलारूस ने रूसी सेना को हमले करने में अपने भू-भाग का इस्तेमाल करने दिया था। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कीव में तीन दिन पहले भी सोमवार जैसाहमला किया गया था। अधिकारियों ने इसे युद्ध की शुरुआत के बाद से कीव पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। रूस, यूक्रेन को हवाई हमले के जरिए परेशान करने की कोशिश कर रहा है।

कीव शहर के प्रशासन ने अपने 'टेलीग्राम' अकाउंट पर बताया कि राजधानी कीव के हवाई क्षेत्र में रूस ने 23 ड्रोन हमले किए, जिनमें से कम से कम 18 ड्रोन को मार गिराया गया। इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि युद्ध में रविवार और सोमवार के बीच देश में कम से कम तीन नागरिकों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि इन ड्रोन हमलों से राजधानी क्षेत्र सहित देश के मध्य और पूर्वी इलाकों समेत कुल 11 क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने 'टेलीग्राम' पर बताया कि दो जिलों शेवचनकिव्स्की और सोलोम्यंस्की में विस्फोट की आवाज सुनी गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है और आपात सेवाएं मौके पर तैनात हैं। सशस्त्र बलों ने कहा कि राजधानी कीव रूस का प्रमुख निशाना प्रतीत हो रही है, लेकिन देश के अन्य इलाकों में भी हमले किए गए हैं। यूक्रेन की वायु सेना ने 'टेलीग्राम' पर बताया कि रूस द्वारा अजोव सागर के पूर्वी तट से दागे गए कम से कम 35 विस्फोटक ड्रोन में से 30 को मार गिराया गया।

यूक्रेन की सेना ने मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन को मार गिराने में लगातार सफलता मिलने का दावा किया है।ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाकर सर्दियों में यूक्रेन के लोगों को परेशान करने के मकसद से रूस, कीव सहित अन्य स्थानों पर बुनियादी ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है। रूस ने शुक्रवार को भी राजधानी कीव पर हमले किए थे। देश भर में कई दर्जन मिसाइलें दागी गईं जिससे व्यापक स्तर बिजली आपूर्ति बाधित हुई। सोमवार को सेंट निकोलस डे था।

ट्विटर कौन चला रहे इसको लेकर कोई निजी राय नहीं, कैसे चला रहा है उसमें रुचि: गुतारेस

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि ट्विटर कौन चला रहा है इसको लेकर उनकी कोई ''व्यक्तिगत भावना'' नहीं है, हालांकि उन्हें इस बात में ''बेहद रुचि'' है कि इस सोशल मीडिया मंच को चलाया कैसे जा रहा है। सोशल मीडिया मंचों पर अभद्र के इस्तेमाल को रोकने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए गुतारेस ने यहां सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, '' मंच कौन चला रहा है इसको लेकर मेरी कोई निजी राय नहीं है। मेरी इस बात में अधिक रुचि है कि मंच को चलाया कैसे जा रहा है।''

गुतारेस से पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि ट्विटर के मालिक एलोन मस्क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं और अगर अरबपति सोशल मीडिया मंच के प्रमुख का पद छोड़ देते हैं तो क्या उन्हें राहत मिलेगी? सीएनएन की खबर के अनुसार, ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने सोमवार को मस्क के मंच के प्रमुख का पद छोड़ने के लिए मतदान किया था। मस्क (51) ने अपने 12.2 करोड़ 'फॉलोअर्स' से पूछा था कि उन्हें ट्विटर के प्रमुख का पद छोड़ना चाहिए या नहीं।

इस 'सर्वेक्षण' पर 1.7 करोड़ वोट आए, जिनमें से करीब 57.5 प्रतिशत लोगों ने 'हां' का विकल्प चुना। मस्क ने रविवार को ट्वीट किया था, '' क्या मुझे ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ देना चाहिए? मैं 'पोल' के परिणाम का पालन करूंगा।'' उन्होंने बाद में एक ट्वीट में कहा,'' जैसा कि कहा जाता है सोच-समझकर कोई की मुराद मांगे, क्योंकि वह पूरी हो सकती है।'' गुतारेस ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और साथ ही अभद्र व उग्रवाद के रूपों से बचाने में सोशल मीडिया मंचों की एक विशेष जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा, '' अगर प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में हो, पत्रकारों को अपना काम करने की अनुमति नहीं दी जाए, साथ ही अभद्र का प्रसार हो तो यह देखकर मुझे काफी दुख होगा।''

उन्होंने कहा, ''इसलिए किसी मंच के मालिक को मेरी यही सलाह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखे, खासकर पत्रकारों की साथ ही यह सुनिश्चित करें कि नव-नाज़ियों, श्वेत वर्चस्ववादियों सहित अभद्र तथा कट्टरपंथी विचारकों को उनके मंच पर अपने हित साधने का मौका न मिले।'' गुतारेस के ट्विटर पर 20 लाख 'फॉलोअर्स' हैं। उनसे पूछा गया कि किन परिस्थितियों में वह अपना खाता बंद करने पर विचार करेंगे और क्या वह मस्क से मिलने में दिलचस्पी रखते हैं?

गुतारेस ने कहा, '' मैं वही करूंगा जो उस समय मेरी अंतरात्मा मुझे करने को कहेगी और जो सही होगा। अभी खाता कायम रखना सही है क्योंकि उसकी एक अहम भूमिका है। हालांकि हम हर स्थिति के प्रति सजग रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि आप किससे मिलते हैं। गुतारेस ने कहा, '' सवाल यह है कि आपके नियम स्पष्ट होने चाहिए स्पष्ट नियम बनाना सोशल मीडिया मंच की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए जरूरी हैं।

आईसीसी रैंकिंग : रिचा घोष आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में चार पायदान आगे बढ़ी

दुबई (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 19 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाने वाली भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में चार पायदान आगे बढ़कर 40वें स्थान पर पहुंच गई हैं। भारत की ही दीप्ति शर्मा रैंकिंग के साप्ताहिक अपडेट के बाद एक पायदान ऊपर 32वें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशलीग गार्डनर ने भी शनिवार को चौथे मैच में अपनी टीम को सात रन से जीत दिला कर पांच मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त दिलाने में अहम योगदान देने पर अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। गार्डनर ने इस मैच में 42 रन बनाने के अलावा दो विकेट भी लिए थे। वह बल्लेबाजों की सूची में एक पायदान ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं। गेंदबाजों की सूची में हालांकि उन्होंने नौ पायदान की छलांग लगाई है और वह 17वें स्थान पर पहुंचने में सफल रही हैं। वह ऑलराउंडरों की सूची में एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई। इस साप्ताहिक अपडेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला के तीसरे और चौथे मैच तथा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दूसरे, तीसरे और चौथे मैच को शामिल किया गया। बल्लेबाजों की सूची में सोफिया डंकले 19 पायदान की छलांग लगाकर 12वें जबकि ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पैरी 17 पायदान आगे बढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गई है।

ईशान किशन की नजर में यह हैं वर्ल्ड के चार बेस्ट कप्तान, सूची में एक भारतीय भी शामिल

मुम्बई (एजेंसी)। नयी दिल्ली। हाल में ही बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जमा कर सुर्खियों में आए युवा क्रिकेटर ईशान किशन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लिमिट ओवर क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के लिए कई मुकाबलों में वह खेल चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल में सबसे ज्यादा रकम में बिकने वाले खिलाड़ी भी ईशान किशन है। हाल में ही एक यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान ईशान किशन ने विश्व के अपने चार पसंदीदा कप्तानों के बारे में बताया है। ईशान किशन ने इसमें पहले नंबर पर भारत के पूर्व कप्तान और विश्वकप विजेता महेंद्र सिंह धोनी को रखा है। महेंद्र सिंह धोनी को ईशान किशन अपना आदर्श भी मानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की तरह ईशान किशन ने भी झारखंड से ही खेला है।

ईशान किशन ने दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को रखा है। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। ईशान किशन ने इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ को रखा है। टेस्ट क्रिकेट में ग्रीम स्मिथ को सबसे शानदार कप्तान के रूप में याद किया जाता है। वहीं, ब्रैंडन मैकुलम को ईशान किशन में चौथे नंबर पर रखा है। ब्रैंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के लिए खेलते रहे हैं। ब्रैंडन मैकुलम लिमिट ओवर क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी थे। वह बेहतर बल्लेबाज के साथ साथ अच्छे विकेटकीपर भी थे। आश्चर्य की बात है कि ईशान किशन में 4 बेस्ट कप्तानों में वर्तमान के किसी भी कप्तान को शामिल नहीं किया है। यहा तक कि उन्होंने अपनी सूची में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी नहीं रखा है।

बेस्ट बल्लेबाज

ईशान किशन से बेस्ट बल्लेबाज के बारे में भी पूछा गया। इसमें उन्होंने पहले नंबर पर विराट कोहली को रखा है। दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ को, तीसरे पर केन विलियमसन और चौथे नंबर पर इंग्लैंड के जो रूट है। टॉप 4 गेंदबाजों में ईशान किशन ने एक नंबर पर जसप्रीत बुमराह को रखा। दूसरे पर मिचेल स्टार्क, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया के ही पैटकमिंस हैं जबकि चौथे पर पाकिस्तान के शहीन शाह अफरीदी हैं। इसके अलावा उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर भी अपनी राय रखी है। रोहित शर्मा के तीन दोहरे शतक पर बात करते हुए ईशान किशन ने साफ तौर पर कहा कि या किसी चमत्कार से कम नहीं है।

भारत/बांग्लादेश: दूसरे टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, रोहित शर्मा के अलावा यह खिलाड़ी भी हुआ टीम से बाहर

मुम्बई (एजेंसी)। भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है। पहला टेस्ट मुकाबला भारत जीत चुका है। वहीं, दूसरा मैच 22 दिसंबर को शुरू होगा। एकदिवसीय श्रृंखला में चोटिल हुए रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी नहीं खेल पाएंगे। दूसरे टेस्ट से रोहित शर्मा की अनुपस्थिति को लेकर बीसीसीआई ने पुष्टी कर दी है। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा है कि रोहित शर्मा अभी भी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान रोहित शर्मा के बाएं अंगूठे में चोट लगी थी। जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा को पूरी तरीके से फिट होने में कुछ वक्त लग सकता है। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

हालांकि, दूसरे टेस्ट से पहले भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया में काफी लंबे समय के बाद शामिल किए गए नवदीप सैनी मांसपेशियों के खिंचाव के कारण दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। नवदीप सैनी अब सीधे नेशनल क्रिकेट अकादमी, बेंगलुरु पहुंचेंगे। यहां नवदीप सैनी की मेडिकल निगरानी की जाएगी। पिछले दिनों रोहित शर्मा के अनुपस्थिति में अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच 22 से 26 दिसंबर के बीच ढाका में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा।

पहले टेस्ट मैच की बात करें तो भारत ने इस से 188 रनों से जीत लिया था और श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की थी। इस मुकाबले में कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच दिया गया था। पहली पारी में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की थी तो वहीं

दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने शानदार शतक जमाया था। भारत के लिए बांग्लादेश दौरा ठीक नहीं रहा है। वनडे श्रृंखला में भारत को हार मिली थी। पहले वनडे में बांग्लादेश 1 विकेट से जीत गया था। दूसरे वनडे में 5 रनों से जीता था। तीसरा वनडे भारत के पक्ष में रहा था। तीसरे वनडे में भारत ने बांग्लादेश को 227 रनों से हराया था। इस मुकाबले में ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था।

वार्नर का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का कोई इरादा नहीं, वार्नर के प्रतिनिधि का बयान

मेलबर्न (एजेंसी)। पिछले कुछ समय से लय हासिल करने के लिए जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी खिलाड़ी डेविड वार्नर को कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दी, लेकिन उनके एजेंट (प्रतिनिधि) ने कहा कि यह आक्रामक सलामी बल्लेबाज की खेल के लंबे प्रारूप को अलविदा कहने की कोई योजना नहीं है। ब्रिस्बेन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच की पहली पारी में वॉर्नर बिना खाता खोले आउट हो गये थे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने तीन रन बनाए।

इस टेस्ट से पहले उन्होंने मौजूदा सत्र की चार पारियों में 5, 48, 21 और 28 का स्कोर बनाया था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट शतक जनवरी 2020 में बनाया था। वार्नर के एजेंट जेम्स एर्स्किन ने कहा कि वह इस बात को नहीं मानते की यह सलामी बल्लेबाज सिडनी में प्रोटियाज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला के समापन पर टेस्ट क्रिकेट छोड़ देगा।

'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' ने एर्स्किन के हवाले से कहा ''नहीं, यह उनका आखिरी टेस्ट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा है तो यह मेरे लिए खबर है।' एर्स्किन ने कहा कि वार्नर की नजरें अगले साल भारत दौरे और इंग्लैंड में एशेज खेली जाने वाली एशेज श्रृंखला पर है। वॉर्नर बॉक्सिंग डे टेस्ट (26 दिसंबर से शुरू होने वाला) खेलकर 100 टेस्ट की उपलब्धि हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के 14वें खिलाड़ी बन जाएंगे।

इस साल 10 टेस्ट मैचों में उनका औसत 21 से कम है लेकिन एर्स्किन का मानना है कि 36 वर्षीय खिलाड़ी जल्द ही बड़ी पारी खेलने वाला है। उन्होंने कहा, '' मुझे लगता है कि वार्नर के बल्ले से रन निकलने वाले है। क्रिकेट के अलावा कई अन्य चीजों में उनकी रूची है लेकिन उन्होंने कभी ऐसी (संन्यास) कोई नहीं की।'

स्वदेश पहुंचने पर अर्जेन्टीना की टीम का भव्य स्वागत

ब्यूनस आयर्स (एजेंसी)। लियोनन मेसी की कप्तानी में कतर में फीफा विश्वकप फुटबॉल जीतकर स्वदेश पहुंची अर्जेन्टीना टीम का भव्य स्वागत हुआ। अर्जेन्टीना की टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर 36 साल बाद खिताब अपने नाम किया है। जिससे अर्जेन्टीना में जश्न का माहौल है। खिताब के साथ वापस लौटी फुटबॉल टीम के स्वागत और उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग सुबह से ही हवाई अड्डे पर पहुंच गये थे। कप्तान मेसी और टीम के राजधानी के ठीक बाहर इजेइजा में तड़के तीन बजे विमान से उतरने पर प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान टीम के लिए लाल कालीन भी बिछाया गया था। विमान से सबसे पहले मेसी विश्व कप ट्रॉफी थामे हुए कोच स्केलोनी के साथ उतरे। ये दोनों इसके बाद एक बैनर के करीब से उतरे जिस पर लिखा था 'धन्यवाद चैंपियन्स'। खिलाड़ियों का स्वागत रॉक बैंड ला मोस्का ने गाते हुए किया। यह गाना एक प्रशंसक ने बैंड के एक पुराने गीत की धुन पर लिखा था और कतर में विश्व कप में अर्जेंटीना के प्रशंसकों के लिए टीम का एक लोकप्रिय अनौपचारिक गीत बन गया था। विश्व

चैंपियन टीम के सदस्य इसके बाद ऊपर से खुली बस में सवार हुए। वे अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (एएफए) के मुख्यालय तक की यात्रा करने के लिए सभी का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक हाईवे पर जुटे थे और अर्जेन्टीना के ध्वज को लहरा रहे थे जिसके कारण बस काफी धीमी गति से चल रही थी। अधिकारियों ने इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखी। प्रयास किया। हवाई अड्डे से एएफए मुख्यालय तक लगभग 11 किलोमीटर की यात्रा करने में बस को लगभग एक घंटे का समय लगा। यहां आतिशबाजी से खिलाड़ियों का आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने मंगलवार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है जिससे देश जीत का जश्न मना सके।

स्वदेश पहुंचने पर उपविजेता फांस की टीम का शानदार स्वागत

पेरिस । फीफा विश्वकप फुटबॉल के खिताबी मुकाबले में हार के बाद भी स्वदेश लौटने पर फ्रांस की टीम का भव्य स्वागत हुआ है। टीम के सेंट्रल पेरिस में हजारों समर्थकों ने उनका नायकों जैसा स्वागत किया। स्टार खिलाड़ी काइलियन एमबापे और उनके साथी स्थानीय रात आठ बजे दोहा से चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर उतरे। खिलाड़ी निराश होकर बाहर आ रहे थे पर हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने उनका 'थैंक यू और 'पेरिस लव यू जैसे बैनरों से स्वागत किया। टीम हालांकि इस पर ध्यान दिये बिना आगे बढ़ गयी। खिलाड़ी हवाई अड्डे से बसों में सवार होकर प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पहुंचे जहां हजारों समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। समर्थकों के उत्साह को देखकर टीम का भी हौंसला बढ़ा। हैरानी की बात यह है कि टीम का ऐसा स्वागत तब भी नहीं हुआ था जब टीम गत विश्वकप में जीत के बाद स्वदेश लौटी थी। जब खिलाड़ी और कोच डिडिएर डेसचैम्प्स होटल की बालकनी में आए तो समर्थकों ने ध्वज लहराकर उनका स्वागत किया।

वेतन नहीं मिलने से नाराज पाक हॉकी कोच एकमैन नीदरलैंड लौटे

कराची । पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच नीदरलैंड के सेगफाइड एकमैन वेतन नहीं मिलने के कारण स्वदेश लौट गये है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कोच एकमैन को आठ माह से वेतन नहीं मिला था। इसके साथ ही वह अपने काम में राजनीतिक हस्तक्षेप से भी परेशान थे। वहीं पीएचएफ से पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) के जरिए उन्हें वेतन दिलाने का आश्वासन दिया था पर एकमैन तैयार नहीं हुए। वहीं पीएचएफ के एक अधिकारी ने कहा कि कोच इसलिए स्वदेश गये हैं क्योंकि राष्ट्रीय टीम को अभी कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना है। इस अधिकारी ने कहा कि इस महीने के अंत तक कोच को पूरा बकाया वेतन दे दिया जाएगा क्योंकि उनका वेतन पीएसबी देता है। गौरतलब है कि पाक हॉकी महासंघ पिछले कुछ साल से आर्थिक संकट से जूझ रहा है जिससे खिलाड़ी भी प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि कोच एकमैन ने जाने से पहले पीएचएफ के एक अधिकारी से कहा था कि टीम खाली पेट और आर्थिक परेशानियों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पाक हॉकी टीम ने हाल ही में मलेशिया में अजलन शाह कप और दक्षिण अफ्रीका में एफआईएच सुपर हॉकी लीग में भाग लिया था और दोनों ही टूर्नामेंटों में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं टीम एशिया कप और राष्ट्रमण्डल खेलों में भी नाकाम रही थी।

नेशन्स कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय टीम ने जमकर जश्न मनाया

-हॉकी इंडिया दो-दो लाख के इनाम देगी

नई दिल्ली । भारतीय महिला हॉकी टीम वेलेंसिया में एफआईएच महिला नेशन्स कप जीतकर स्वदेश लौटी है। भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबले में स्पेन की टीम को 1-0 से हराया था। इसी के साथ ही भारतीय महिला टीम ने 2023-24 प्रो लीग का टिकट हासिल कर लिया है। जीत के साथ लौटी भारतीय टीम के जश्न मनाने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें भारतीय टीम ट्रॉफी लिए हुए अपने ही अंदाज में डांस करती हुई दिखी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी आया है। जिसे हॉकी इंडिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। नेशन्स कप के फाइनल में भारत की ओर से गुरजीत कौर ने छठे मिनट में ही पेनल्टी कार्नर से गोल कर भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद दोनो ही टीमें कोई गोल नहीं कर पायीं ओर इस प्रकार भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम किया। वहीं हॉकी इंडिया ने इस जीत पर खुश व्यक्त करते हुए टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही भारतीय सहायक स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को भी एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया

कराची (एजेंसी)। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीसरे टेस्ट में हराने के साथ ही तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। इससे पाक टीम के कप्तान बाबर आजम को करारा झटका लगा है। इंग्लैंड ने मंगलवार को पाक को तीसरे टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट 8 विकेट से जीता। उसे जीत के लिए 167 रन का लक्ष्य मिला था। 111 रन की शतकीय पारी खेलने वाले हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। उन्होंने सीरीज में 468 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी उन्हें ही मिला। पाकिस्तान ने पहली पारी में 304

जबकि दूसरी पारी में 216 रन बनाए थे जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 354 रन बनाकर 50 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी।

इंग्लैंड ने पहली बार पाकिस्तान में सभी टेस्ट मैच जीते हैं। वहीं पाक को घर में पहली बार लगातार 4 टेस्ट हारने के अलावा क्लीन स्वीप से हार भी मिली। इससे पहले उसे ऑस्ट्रेलिया से भी अंतिम टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार आजम ने एक ऐसा खराब रिकॉर्ड अपने नाम किया है जिसे वह भूलना चाहेंगे।

पाक की टीम घर में 1955 से टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। इस दौरान आजम सहित 26 खिलाड़ी बतौर कप्तान उतरे हैं पर किसी भी बार लगातार दो सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं हुआ। इस तरह से आजम ने पिछले 25 कप्तानों की मेहनत बेकार कर दी। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और 20 दिसंबर को उसने सीरीज गंवा दी। यानी 20 दिन में टीम ने घर में 67 साल का खराब रिकॉर्ड बना दिया है।

बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल की बैठक में होगा अलग-अलग कोच और कप्तान पर फैसला

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की एपेक्स काउंसिल की बैठक बुधवार को होगी। इसमें भारतीय टीम के लिए अलग-अलग प्रारुप में अलग-अलग कोच रखने को लेकर फैसला होगा। हाल के दिनों में टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टीम को एशिया कप और टी20 विश्वकप में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में मुख्य कोच राहुल द्रविड़ पर भी सवाल उठे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि टीम के लिए टी20 प्रारुप में अलग कोच होना चाहिये। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने भी हाल में संकेत दिये थे कि कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एपेक्स काउंसिल की बैठक में द्रविड़ पर काम के बोझ को कम करने पर भी बात होगी। इसके साथ ही टेस्ट एकदिवसीय के साथ ही टी20 प्रारुप में भी अलग कोच बनाया जा सकता है।

कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अलग-अलग प्रारुपों में टीम के लिए अलग कप्तान और कोच को रखे जाने की मांग की है। द्रविड़ अभी तीनों ही प्रारुपों में मुख्य कोच ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ऐसे में उनपर काम का बोझ बढ़ना स्वाभाविक है। इस बैठक में उनपर पड़ने वाले भार को कम करने के साथ ही अलग-अलग प्रारुपों में अलग कप्तान पर भी बात होगी। पिछले कुछ समय में कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन नीचे आया है और उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में उनकी जगह पर हार्दिक पंड्या को टी20 प्रारुप की कप्तानी सौंपने की मांग की जा रही है। पंड्या के पास न्यूजीलैंड और आयरलैंड के खिलाफ टीम की कप्तानी का अनुभव भी है।

फांस के फारवर्ड बेनजेमा ने संन्यास लिया

पेरिस । फांस के फारवर्ड करीम बेनजेमा फीफा विश्वकप के खिताबी मुकाबले में हार से इतने निराश हुए हैं कि उन्होंने खेल से दूर होने का फैसला किया है। बेनजेमा ने फांस की अर्जेन्टीना के खिलाफ हार के बाद सोशल नेटवर्क पर एक संदेश पोस्ट कर कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह रहे हैं। बेलोन डियोर पुरस्कार विजेता बेनजेमा इस बार अभ्यास मुकाबलों में ही मांसपेशियों में खिंचाव के कारण विश्वकप नहीं खेल पाये थे। बेनजेमा ने अब अपने 35वें जन्मदिन पर फांस की शर्ट में अपनी एक तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा ''मैं आज जहां हूं वहां पहुंचने के लिए मैंने प्रयास किया और गलतियां की और मुझे इस पर गर्व है! मैंने अपनी कहानी लिख ली है और हमारी कहानी समाप्त हो रही है।'' रीयाल मैड्रिड की ओर से खेलने वाले स्ट्राइकर बेनजेमा साल 2014 विश्व कप में फ्रांस के शीर्ष स्कोरर था पर साल 2018 विश्व कप में वह शामिल नहीं किये गये थे। तब उन्हें साथी खिलाड़ी मैथ्यू वालबुएना के साथ सेक्स-टेप प्रकरण में रही भूमिका के कारण बाहर कर दिया गया था। उस मामले से बेनजेमा को करियर में नुकसान के साथ ही आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। वह अक्टूबर 2015 से लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रहे पर पिछले साल मई में कोच दिदिएर डेसचैम्प्स के आने के बाद उनकी टीम में वापसी हुई। बेनजेमा ने वापसी के बाद फांस के लिए 16 मैच में 10 गोल किए और काइलियान एमबापे के साथ शानदार जोड़ी बनाई। पिछले साल की यूरोपीय चैम्पियनशिप में वह चार गोल के साथ फांस के शीर्ष स्कोरर थे।

न्यूजीलैंड ने भारत-पाक दौरे के लिए घोषित की टीम

-भारत दौरे पर नहीं आयेंगे विलियम्सन और कोच स्टीड

ऑकलैंड । न्यूजीलैंड टीम ने नये साल में होने वाले भारत और पाकिस्तान दौरे के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। न्यूजीलैंड की टीम पहले पाक दौरे पर जाएगी। पाक के खिलाफ इस दौरे की शुरुआत एकदिवसीय सीरीज के साथ ही 10 जनवरी से होगी। इसके बाद कीवी टीम भारत दौरे पर पहुंचेगी। न्यूजीलैंड टीम भारत दौर में नये कोच के साथ पहुंचेगी। भारत के खिलाफ इस सीरीज का पहला मुकाबला 18 जनवरी को होगा। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियम्सन और कोच गैरी स्टीड पाक दौरे के बाद स्वदेश लौट जाएंगे और टीम कप्तान टॉम लैथम व मुख्य कोच ल्यूक रोंकी के साथ भारत दौरे पर पहुंचेगी। विलियम्सन और स्टीड के अलावा टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज टिम साउदी भी भारत दोने में शामिल नहीं किये गये हैं। उनकी जगह पर जैकब डफी और विलियम्सन की जगह पर मार्क चैपमैन को टीम में शामिल किया गया है। वहीं गैर अनुभवी खिलाड़ी हेनरी शिपले को भी घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन को देखते हुए भारत दौरे के लिए जगह दी गयी है। ईश सोढ़ी और हेनरी निकोल्स दोनो ही दौरों में रहेंगे।

पाक के खिलाफ न्यूजीलैंड का दल

केन विलियम्सन (कप्तान) टॉम लैथम फिन एलेन माइकल ब्रेसवेल डेवोन कानवे लॉकी फर्ग्यूसन मैट हेनरी एडम मिल्ने डेरिल मिचेल हेनरी निकोल्स ग्लेन फिलिप्स मिचेल सैंटनर हेनरी शिपली ईश सोढ़ी टिम साउदी।

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का दल

टॉम लैथम (कप्तान) फिन एलेन माइकल ब्रेसवेल मार्क चैपमैन डेवोन कॉनवे जैकब डफी लॉकी फर्ग्यूसन मैट हेनरी एडम मिल्ने डेरिल मिचेल हेनरी निकोल्स ग्लेन फिलिप्स मिचेल सैंटनर हेनरी शिपली ईश सोढ़ी टिम साउदी।

सूर्यकुमार यादव की पर्फोर्मेंस में इस कारण आता है विस्फोट, मैच से पहले करते हैं ये काम

दुबई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने वर्ष 2022 में टी20 क्रिकेट में जो शानदार खेल दिखाया है उसके बाद से वो फैंस के पसंदीदा खिलाड़ी बन गए हैं। टी20 और वनडे मुकाबलों के मद्देनजर सूर्यकुमार यादव के नाम ही पूरा 2022 रहा है।

अपने दमदार प्रदर्शन के कारण सूर्यकुमार यादव टी20 विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए है। इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान कई शानदार रिकॉर्ड भी बनाए है। सूर्यकुमार यादव ने टी20 क्रिकेट में एक वर्ष में ही दो शतक जड़कर रिकॉर्ड कायम दिया है। सूर्यकुमार यादव बताते हैं कि मैच के दौरान उनका ध्यान सिर्फ खेल पर होता है।

सूर्यकुमार यादव के अनुसार वो मैच के दौरान वो डगआउट के पास बैठकर पूरा गेम देखने पर फोकस रखते है। इस दौरान उनका पूरा फोकस सिर्फ मैच पर होता है। इस दौरान वो टीवी सेट पर भी नजर नहीं डालते है। उन्होंने कहा कि बैटिंग के लिए मुझे क्रीज पर उतरने से पहले वार्म अप करना होता है। बैटिंग के लिए जाने से पहले तेज दौड़ना रूटिन में शामिल है। इसके अलावा खेल के दौरान हर दूसरी गेंद पर स्ट्रेचिंग भी करता हूं ताकि क्रीज पर रहने के दौरान पैरों को दिक्कत ना हो। तेज भागने के लिए बैटिंग से पहले वार्मअप करना बहुत जरुरी होता है।

फिल्में देखने का भी शौक

सूर्यकुमार यादव कई बार मैच के पहले फिल्में भी देखना पसंद करते हैं। आमतौर पर कॉमेडी फिल्मों को वो देखते है, जिसमें अपना अपना, चुप चुप के, गोलमाल, हलचल और हेरा फेरी जैसी फिल्में देखना शामिल है। उनका कहना है कि ये फिल्में कई बार देखी है। इन फिल्मों को फोन पर भी देखना पसंद है।

रणजी में शामिल हुए सूर्यकुमार

घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का आयोजन हो रहा है। सूर्यकुमार यादव यहां मैदान पर बल्ले से धमाल मचाते दिखेंगे। इससे पहले बीते तीन सालों तक सूर्यकुमार ने रणजी में हिस्सा नहीं लिया था मगर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका नहीं मिलने पर उन्होंने फिर से रणजी की तरफ रुख किया है। बता दें कि वो मुंबई की ओर से खेलते है। 20 दिसंबर को रणजी ट्रॉफी के लिए हैदराबाद और मुंबई के बीच मुकाबला होना है, जिसकी टीम में सूर्यकुमार भी शामिल है।

ऐसा है सुर्यकुमार यादव का स्कोर

बता दें कि वर्तमान में सूर्यकुमार यादव रणजी ट्रॉफी में खेल रहे है। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रखा गया था।

इस वर्ष सूर्यकुमार ने 31 टी20 पारियां खेली है, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 190 का रहा। इस साल सूर्यकुमार के बल्ले से कुल 1164 रन निकले है। बता दें कि कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले सूर्यकुमार पहले भारतीय बल्लेबाज है। इस साल उनके बल्ले से दो टी20 शतक और नौ अर्धशतक निकले है।

जहरीली शराब मामले की हो सीबीआई जांच : चिराग

'बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन'

राजेश अलख

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर । लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौतों के मामले में राज्य की नीतीश कुमार नीत सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की।

लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए चिराग पासवान ने कहा, मैं अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस सदन में आया हूं। जहरीली शराब के कारण एक के बाद एक मौत से राज्य में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। उन्होंने राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।

चिराग ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार एवं राज्य का प्रशासनिक तंत्र इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक समाचार चैनल के स्टिंग आपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में सभी को इस बात की जानकारी है कि शराबबंदी के बावजूद किस प्रकार से हर जगह शराब की बिक्री की जा रही है।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद ने कहा, लेकिन इसके बावजूद राज्य में महागठबंधन के नेता इस विषय पर खामोश हैं क्योंकि इसमें उनकी संलिप्तता है। जमुई के सांसद ने कहा, मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार इस मामले में स्वत: संज्ञान ले और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए। उन्होंने इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की।

मोटे अनाज को 'जन आंदोलन' बनाने की दिशा में काम करें, बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी की सलाह

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसदीय दल की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज और खेलों की अहमियत पर बल दिया और सांसदों से इन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद परिसर में सांसदों के लिए आयोजित एक विशेष दोपहर भोज में भी हिस्सा लिया, जिसमें मोटे अनाजों के व्यंजन परोसे गए। संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा कि देश के ज्यादातर छोटे किसानों द्वारा उगाए जाने वाले मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाना देश की सेवा करने के बराबर है।

जोशी के मुताबिक मोदी ने कहा, यह एक 'जन आंदोलन' का स्वरूप लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने उनकी सरकार के अनुरोध पर 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है क्योंकि उन्होंने मोटे अनाज को भोजन का एक लोकप्रिय विकल्प बनाने का आह्वान किया था। भारत की अध्यक्षता में जी-20 से जुड़ी बैठकों में हजारों विदेशी प्रतिनिधियों के बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना के बीच मोदी ने कहा कि मोटे अनाज को उनके लिए परोसे जाने वाले भोजन व व्यंजनों का हिस्सा बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को आंगनवाड़ियों, स्कूलों, घरों और सरकारी बैठकों में भी उपयोग किया जा सकता है।

मोदी ने कहा कि अनाज के बारे में जागरूकता स्कूलों और कॉलेजों में परिचर्चा की मेजबानी करके फैलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि उच्च पोषण वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी लोगों के साथ साझा की जाती है तो उसका उपभोग भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सांसद अपनी मेजबानी में होने वाली बैठकों में मोटे अनाज से बने व्यंजनों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की श्रेणी में आने वाले 85 प्रतिशत से अधिक भारतीय किसान बड़ी संख्या में बाजरा उगाते हैं, ऐसे में इन अनाजों की खपत में वृद्धि से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। संयोग से, सरकार ने मंगलवार को सभी सांसदों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी भी की। इस आयोजन के केंद्र में मोटे अनाज से बने व्यंजन रहे।

सांसदों के साथ दोपहर भोज में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जब हम 2023 को मोटे अनाज के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं, संसद में शानदार दोपहर के भोज में मैं शामिल हुआ, जहां मोटे अनाज के व्यंजन परोसे गए। पार्टी लाइन से परे से भागीदारी देखकर अच्छा लगा। उन्होंने एक तस्वीर साझा की, जिसमें राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोपहर के भोजन के दौरान उनके साथ बैठे थे। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कबड्डी जैसे भारतीय खेलों पर विशेष ध्यान देने के साथ खेल संबंधी बैठकों को बढ़ावा देने के लिए भी कहा। पिछले कुछ वर्षों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन और उनकी मेजबानी करना भाजपा की प्रमुख पहलों में से एक रहा है।

जयशंकर कब कहेंगे कि 2020 से पहले की स्थिति बहाल करना मुख्य उद्देश्य है : जयराम रमेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। कांग्रेस ने चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा संसद में दिए बयान को लेकर मंगलवार को सवाल किया कि जयशंकर स्पष्ट रूप से कब यह घोषणा करेंगे कि भारत का मुख्य उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल करना है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि सरकार चीन को लेकर 1986 और 2013 की तरह आक्रामक रुख क्यों नहीं अपना रही है कि चीन अपने सैनिकों को पीछे हटा ले? उन्होंने एक बयान में कहा, हम विदेश मंत्री की इस बात से सहमत हैं कि हमारे जवानों का सम्मान और सराहना होनी चाहिए क्योंकि वे हमारे शत्रुओं के खिलाफ मजबूती से खड़े रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री का यह कहना जवानों का सम्मान था कि हमारी सीमा में न कोई घुस आया है और न कोई घुसा हुआ है?

प्रधानमंत्री ने यह बात उस वक्त की थी जब हमारे 20 जवान सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए। रमेश ने यह भी कहा, विदेश मंत्री ने दावा किया कि चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हैं। फिर आपने (जयशंकर) चीनी राजदूत को तलब कर डिमार्के (आपत्ति जताना और स्पष्टीकरण) क्यों जारी नहीं किया जैसे हम पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ करते हैं? उन्होंने सवाल किया, चीन के साथ हमारे व्यापार की निर्भरता इतने रिकॉर्ड स्तर पर क्यों है कि 2020-21 में आयात 95 अरब डॉलर और व्यापार घाटा 74 अरब डॉलर तक पहुंच गया? हमारे सैनिकों ने सितंबर, 2022 में 'रूस वोस्तोक 22' में चीन के साथ युद्धाभ्यास क्यों किया?

रमेश का कहना है, विदेश मंत्री ने कहा कि हम चीन को एकतरफा ढंग से एलएसी की स्थिति नहीं बदलने देंगे। क्या पिछले दो वर्षों से यथास्थिति नहीं बदली है कि चीन के सैनिक डेपसांग में 18 किलोमीटर भीतर की तरफ हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिक 1000 वर्गकिलोमीटर के क्षेत्र में पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां वे पहले गश्त किया जा करते थे?'

उन्होंने सवाल किया, क्या यह स्थिति बदलना नहीं हुआ कि हमने ऐसे बफर जोन पर सहमति जता दी कि हमारे जवान उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते जहां वे पहले गश्त करते थे? विदेश मंत्री कब स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करना हमारा मुख्य उद्देश्य है?

रमेश ने कहा, विदेश मंत्री बोले कि हम चीन पर दबाव डाल रहे हैं।' अगर ऐसा है तो फिर हमने विशुद्ध रूप से प्रतिक्रिया करने का ही रुख क्यों अपना रखा है? 2020 से पहले की यथास्थित बहाल करने का पूरा भरोसा मिले बिना हमने कैलाश रेंज में अपने स्थानों से पीछे क्यों हटा लिया?

उन्होंने पूछा, हम उस तरह से आक्रामक क्यों नहीं है कि चीन अपने सैनिकों को पीछे हटा ले जैसे 1986 और 2013 में हुआ था। हम धारणा के अंतर' का हवाला देकर कब तक चीनी आक्रमकता को सही ठहराते रहेंगे? ऐसा करना कब बंद होगा?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के परोक्ष संदर्भ में कहा था कि राजनीतिक मतभेद और आलोचनाओं में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जवानों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सैनिकों के लिए पिटाई' शब्द का इस्तेमाल कर उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए।

लोकसभा में समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, यदि चीन के प्रति भारत का रुख उदासीन होता तो सीमा पर सेना को किसने भेजा?, हम चीन पर सैनिकों की वापसी के लिए दबाव क्यों बनाते और हम सार्वजनिक रूप से क्यों कहते कि हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि देश के जवान यांगत्से में 13 हजार फुट की ऊंचाई पर डटे हैं और सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं।

जरूरी पड़ी तो हर दिन कार्यस्थगन कर चर्चा कराने से संकोच नहीं करूंगा : धनखड़

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को उच्च सदन के सदस्यों को आश्वस्त किया कि स्थिति की गंभीरता के अनुरूप यदि जरूरत पड़ी तो वह हर दिन नियम 267 के तहत कार्यस्थगन के नोटिस स्वीकार कर सदन में चर्चा कराने से भी संकोच नहीं करेंगे।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पूरे कार्यकाल के दौरान यदि ऐसा कोई नोटिस सही प्रारूप में नहीं मिला तो वह एक भी बार उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा नियम 267 के तहत दिये गये विभिन्न नोटिस को आसन द्वारा लगातार खारिज किए जाने पर सदस्यों की आपत्ति के बाद धनखड़ ने शून्यकाल के दौरान यह बात कही।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की एक टिप्पणी को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद जैसे ही सदन में व्यवस्था बहाल हुई और कार्यवाही आगे बढ़ी, सभापति धनखड़ ने कहा कि आज उन्हें नियम 267 के तहत कार्यस्थगन कर चर्चा कराने के लिए छह नोटिस मिले हैं।

सभापति ने कहा कि इनमें से एक नोटिस समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव का है, जिसे देखकर लगा कि उन्होंने इसे सौंपने से पहले इस पर होमवर्क किया है।

धनखड़ ने कि इस नोटिस में उन्होंने दो गलतियां की है, जिसकी वजह से उनका नोटिस अस्वीकार कर दिया गया है।

धनखड़ ने बताया कि यादव के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि सदन की नियमावली में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराए जाने के संदर्भ में नियम 176 व 180 उपलब्ध हैं...पर इन नियमों के तहत संबंधित मंत्री की सहमति की आवश्यकता है।

धनखड़ ने कहा, मंत्री की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यह सदन किसी सदस्य या मंत्री की सहमति से कोई भी कामकाज नहीं करता है। अनुमति मेरी होती है। इसके अलावा कोई भी नोटिस ऐसा नहीं है, जो नियमो के अनुरूप है।

बाकी सभी नोटिस अस्वीकार करते हुए उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे नियमों का पालन करें और उसके अनुरूप मुद्दे उठाएं।

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने इस पर आपत्ति जताते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि वह सभापति के शुक्रगुजार है कि वह नियम 267 को चर्चा के केंद्र में लेकर आए हैं।

उन्होंने सदन की परिपाटियों का हवाला देते हुए कहा कि 2016 से 2022 तक जब तक एम. वेंकैया नायडू सभापति रहे, उन्होंने 267 के तहत एक भी नोटिस नहीं स्वीकार किया।

डेरेक ने कहा, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शंकर दयाल शर्मा ने 1990 से 1992 के बीच नियम 267 के तहत चार नोटिस स्वीकार किए। भैरो सिंह शेखावत ने नियम 267 के तीन नोटिस स्वीकार किए और हामिद अंसारी ने चार नोटिस स्वीकार किए।

उन्होंने कहा, आपके पूर्ववर्तियों ने इस नियम के तहत नोटिस स्वीकार किए हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि हर सप्ताह या महीना इस नियम के तहत नोटिस स्वीकार नहीं किए जा सकते लेकिन 267 एक जीवंत नियम है। जिसे साल में दो या तीन बार स्वीकार किया जा सकता है।

इस पर सभापति ने कहा, क्विज मास्टर ने कुछ आंकड़े रखे हैं। सभापति की इस टिप्पणी पर डेरेक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं। उन्होंने कहा, क्विज मास्टर के रूप में मैं 2011 में सेवानिवृत्त

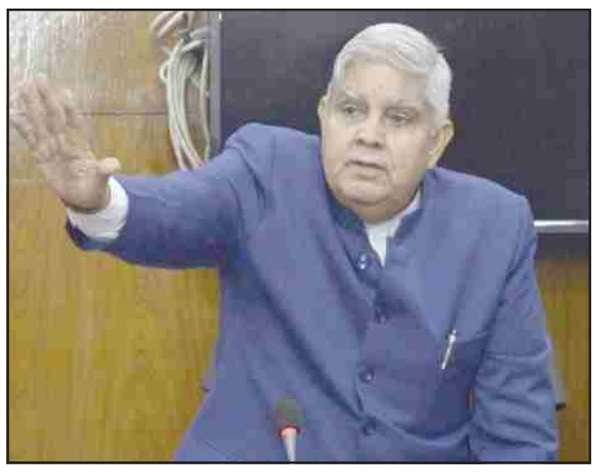

हो चुका हूं। मैं आज जो हूं उसके अनुरूप मुझसे व्यवहार कीजिए।

इसके बाद धनखड़ ने कहा कि उन्होंने तो अभी अपने कार्यकाल की शुरुआत की है।

उन्होंने कहा, मेरे पास स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखने के लिए पर्याप्त समय है और यदि ऐसा अवसर आता है कि प्रतिदिन नियम 267 को स्वीकार करना पड़े...तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं इसे लागू करने में संकोच नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा, और अगर मेरे पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी इसे लागू करने का कोई अवसर नहीं आया तो मैं नहीं करूंगा। इसकी (नोटिस) जांच गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि विपक्षी सदस्य शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही हर दिन नियम 267 के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर प्रति दिन पांच से नौ नोटिस दे रहे हैं लेकिन आसन की ओर से नियमों का हवाला देकर उनके नोटिस अस्वीकार कर दिए गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष खरगे ने भी कल सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि आसन की ओर से उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव को नियमों के तहत नहीं होने का कारण बताते हुए खारिज किये जाने से मीडिया में यह संदेश जा रहा है कि विपक्ष को सदन के नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे सभी नोटिस में नियमों का समुचित हवाला दिया जाता है।

भारत जोड़ो यात्रा से हिली एनडीए सरकार : गहलोत

जयपुर, 20 दिसम्बर (एजेन्सी)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा' कामयाबी के साथ जारी है और यात्रा ने केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को हिला दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह घबरा गए हैं। यात्रा के साथ चल रहे गहलोत ने यहां आयोजित दैनिक संवाददाता सम्मेलन में यह दावा किया। यात्रा की सफलता की बात करते हुए उन्होंने कहा,यात्रा का जहां तक सवाल है ... मैं समझता हूं कि इसने राजग सरकार को हिलाकर रख दिया है।

प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी जी, (गृहमंत्री) अमित शाह जी घबरा गए हैं। भाजपा के (जेपी) नड्डा साहब व अन्य भाजपा वाले विचलित हो गए हैं... चिंतित हो गए हैं। इसके साथ ही गहलोत ने 'मुख्यधारा की मीडिया' पर यात्रा को उचित कवरेज नहीं देने का आरोप दोहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया पर उनका कवरेज नहीं करने का दबाव है और मीडिया इस दबाव में आ रहा है।

गहलोत ने कहा कि यात्रा महंगाई, बेरोजगारी व सामाजिक सद्भाव जैसे सामाजिक सरोकार लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है और यह रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रा बहुत कामयाबी से चल रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया किया कि हजारों लोगों का यात्रा के इंतजार में घंटों खड़े रहना क्या दर्शाता है।

यात्रा के सक्रिय राजनीति से संबंधों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की यात्रा का राजनीति से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन राजनीति में हर गतिविधि चाहे कोई धरना हो या प्रदर्शन, उसका एक संदेश होता है। उन्होंने कहा कि इसमें राहुल गांधी पूरी तरह कामयाब हुए हैं। गहलोत ने कहा कि यात्रा का राजस्थान में बहुत प्रभाव रहा है और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां के लोग इसमें नहीं आए।

गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य को कानूनी अधिकार बनाने के लिए केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (जिसके तहत 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है) का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 'कोई भी भूखा न सोए' इसके लिए भी संसद में एक कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वह राज्य के आगामी बजट में ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि ऐप आधारित सेवाओं के श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई योजना पेश करेंगे। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने सोमवार को ऐसे श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में बात की थी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा

भी प्रदान की जानी चाहिए।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में यात्रा बहुत सफल रही और राजस्थान में आज आखिरी दिन है। यात्रा राजस्थान में लगभग 485 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार को हरियाणा में प्रवेश करेगी। रमेश ने यात्रा के लिए राजस्थान में की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और 10 में से 10 अंक दिए।

रमेश ने बताया कि यात्रा में नौ दिनों का अवकाश रहेगा और इस दौरान अन्य राज्यों के यात्री अपने घर जाएंगे और यात्रा के साथ चलने वाले कंटेनर रखरखाव के काम के लिए भेजे जाएंगे। गांधी और अन्य नेता 24 दिसंबर की रात को अवकाश के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। नौ दिनों के विराम के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी तो यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा (द्वितीय चरण), पंजाब और जम्मू-कश्मीर को कवर करेगी। इससे पहले यात्रा सुबह अलवर के कटी घाटी पार्क से शुरू हुई और लोहिया का तिजारा में दोपहर का विराम हुआ। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी सुबह यात्रा में हिस्सा लिया।

डियर साप्ताहिक लॉटरी
कूचबिहार निवासी ने ₹1 करोड़ जीते

कूचबिहार, पश्चिम बंगाल के श्री जगदीश बर्मन ने **11.11.2022** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **87H 11421** है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार विजेता टिकट जमा कर दी है। ''मुझे एक करोड़पति बनाने के लिए मैं डियर लॉटरी और नागालैंड स्टेट लॉटरीज के प्रति अपना पूरा आभार व्यक्त करता हूं। डियर लॉटरी समूचे पश्चिम बंगाल राज्य में काफी सारे करोड़पति बना रही है। यह विशाल पुरस्कार राशि हमारे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने तथा जीवन में बचत करने में भी हमारी सहायता करेगी।'' विजेता ने कहा।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com